घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 117- गुरूवार 26- फरवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस पार्टी अपने युवा निडर सिपाहियों के साथ खड़ी : प्रियंका गांधी वाड्रा

नई दिल्ली,25 फरवरी 2026। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस द्वारा इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने युवा निडर सिपाहियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट कर लिखा कि सत्य के लिए शांतिपूर्ण एवं अहिंसक प्रतिरोध हमारी गौरवशाली विरासत है जो हमें महात्मा गांधी और लाखों-करोड़ों भारतीय पूर्वजों से मिली है। दुनिया भर के दबाव में झुककर,भारत के हितों से समझौता करने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में 140 करोड़ भारतवासियों का हित है। जनता की आवाज उठाने के लिए युवा कांग्रेस के साथियों पर कार्रवाई अत्यंत निंदनीय एवं शर्मनाक है। दरअसल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जो लोग जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं,जो आम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर सरकार का विरोध करना जुर्म है, तब कांग्रेस का हर व्यक्ति यह जुर्म बार-बार करेगा। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मां रजनीबाला ने कहा कि चिब को सोमवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रदर्शन को साजिश बताया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि देश में विरोध करना कब से साजिश होने लगा।

ईडी ने अनिल अंबानी का मुंबई स्थित घर 'एबोड' किया कुर्क

3716 करोड़ रुपये है कीमत

नई दिल्ली,25 फरवरी 2026। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत अनिल अंबानी के मुंबई पॉश इलाका स्थित घर 'एबोड' को कुर्क किया है, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को दी गई जानकारी में बताया कि रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर 'एबोड' को ईडी ने कुर्क किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी उनके समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में इस बहुमंजिला घर को कुर्क किया है। ईडी ने ये कार्रवाई धनशोधन रोधक कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत की है। मुंबई के पाली हिल स्थित 66 मीटर ऊंचा यह आलीशान घर 17 मंजिला है। कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 3,716.83 करोड़ रुपये है। जानकारी के मुताबिक अनिल अंबानी पूछताछ के दूसरे दौर के लिए यहां ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। उन्होंने पहली बार अगस्त, 2025 में ईडी के सामने पेश होकर पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। केंद्रीय जांच एजेंसी के इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गया है।

स्टेज पर दुल्हन ने उठाई जयमाला,नकाबपोश आशिक ने दुल्हन को मारी गोली

बिहार,25 फरवरी 2026। बिहार के बक्सर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ शादी की खुशियां चंद मिनटों में मातम में बदल गईं। मंगलवार की रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नगर चौसा पंचायत स्थित मल्लाह टोला में जयमाला की रस्म चल रही थी। दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर एक-दूसरे के सामने खड़े थे, तभी एक नकाबपोश युवक भीड़ को चीरते हुए स्टेज पर चढ़ा और 18 वर्षीय दुल्हन आरती कुमारी के पेट में सरेआम गोली मार दी। तेज बज रहे डीजे के गानों के शोर में गोली की आवाज तो दब गई,लेकिन जैसे ही आरती लहूलुहान होकर स्टेज पर गिरी,पूरे समारोह में अफरा-तफरी मच गई। गोली लगने के बाद परिजन आनन-फानन में आरती को लेकर बक्सर सदर अस्पताल भागे। रास्ते में दर्द से तड़पती दुल्हन बार-बार अपने पेट की चोट दिखाती रही और हमलावर का नाम लेती रही। उसने स्पष्ट रूप से कहा,'दीनबंधु ने मुझे गोली मार दी है।' अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे वाराणसी (बनारस) रेफर कर दिया।

इजरायल पहुंचे पीएम मोदी,नेतन्याहू ने गले लगाकर किया स्वागत....

इजराइली संसद में पीएम मोदी बोले...जिस दिन मेरा जन्म हुआ,उसी दिन भारत ने इजराइल को मान्यता दी

तेल अवीव,25 फरवरी 2026। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइली संसद नेसेट में संबोधन देने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के इजराइल दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ,उसी दिन भारत ने इजराइल को मान्यता दी नेसेट को संबोधित करने मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। संसद पहुंचने पर सांसदों ने मोदी का खड़े होकर स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी से पहले इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी इजराइल के ग्रेट फ्रेंड हैं। इजराइली

पीएम ने कहा कि मोदी मेरे भाई जैसे हैं, मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है। उन्होंने मोदी को दुनिया का सम्मानित नेता बताया। इससे पहले नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया। इस दौरान राष्ट्रगान की धुन के साथ पीएम का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी और नेतन्याहू ने राजधानी तेल अवीव में प्राइवेट बातचीत भी की। इसके बाद वे होटल पहुंचे जहां, प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कलाकारों ने परफोर्मेंस भी दी। मोदी का यह 9 साल बाद दूसरा इजराइल दौरा है। इससे पहले वे जुलाई 2017 में तेल अवीव गए थे।

मोदी बोले...इजराइली संसद में खड़े होना सम्मान की बात

इजराइली संसद को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि इस सदन के समक्ष उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और एक प्राचीन सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में दूसरी प्राचीन सभ्यता को संबोधित कर रहा हूं। मैं 14 लाख भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं और मित्रता, सम्मान और साझेदारी का संदेश लेकर आया हूं।

नेतन्याहू बोले....भारत में कभी यहूदियों पर अत्याचार नहीं हुआ

नेतन्याहू ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक ऐसी सभ्यता है,जहां यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इतिहास में कई देशों में यहूदियों को परेशान किया गया, लेकिन भारत ने हमेशा उन्हें अपनाया और सम्मान दिया। नेतन्याहू ने कहा- भारत एक ऐसी सभ्यता है जहां यहूदियों का स्वागत किया गया। हम इसे कभी नहीं भूलते। धन्यवाद,भारत।

'ज्यूडीशियल करप्शन' चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब की बिक्री पर रोक

न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे : जस्टिस सूर्यकांत

नई दिल्ली,25 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद 'ज्यूडीशियल करप्शन' चैप्टर वाली एनसीईआरटी किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। एनसीईआरटी किताब से विवादित हिस्सा हटाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार,एनसीईआरटी ने चैप्टर का सुझाव देने वाले एक्सपर्ट्स और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की इंटरनल मीटिंग बुलाई है। किताब को वेबसाइट से भी हटा लिया गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया था। सिब्बल ने सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच को बताया कि क्लास 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है। यह निंदनीय है। सिंघवी ने कहा कि एनसीईआरटी ने मान लिया है कि राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और अन्य संस्थानों में भ्रष्टाचार है ही नहीं। सूर्यकांत ने कहा...दुनिया में किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह एक सोची-समझी और गहरी साजिश लगती है। मुझे पता है इससे कैसे निपटना है। मैं यह केस खुद हैंडल करूंगा। हम इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहते।

सरकारी सूत्रों ने कहा...शासन के तीनों अंगों को जोड़ना चाहिए था : एनसीईआरटी चेयरमैन दिनेश प्रसाद सकलानी का इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं आया है। काउंसिल के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए वे इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। इस बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि भले ही एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस संस्था है, लेकिन चैप्टर जोड़ने से पहले अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए था। सरकारी सूत्रों ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा शामिल करना था,तो उसमें शासन के तीनों अंगों-कार्यपालिका,न्यायपालिका और विधायिका को भी जोड़ा जाना चाहिए था। सरकारी सूत्रों ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित आंकड़े संसदीय अभिलेखों और नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड में मौजूद हैं,लेकिन फैक्ट्स के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए केंद्र से परामर्श नहीं लिया गया।

एनसीईआरटी की नई सोशल साइंस टेक्स्टबुक में चैप्टर था

एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस की नई टेक्स्टबुक जारी की थी। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। किताब का नाम 'एक्सप्लोरिंग सोसायटी: इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2' है। इसमें 'द रोल ऑफ द ज्यूडीशियरी इन अवर सोसायटी' चैप्टर के अंदर 'करप्शन इन द ज्यूडिशियरी' का टॉपिक जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में पेंडिंग मामले और जजों की भारी कमी ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं। जज आचार संहिता से बंधे होते हैं, जो न केवल कोर्ट में उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है, बल्कि कोर्ट के बाहर उनके आचरण को भी तय करती है।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना...

कोलकाता,25 फरवरी 2026। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही भारत निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग गुप्त रूप से 1.20 करोड़ वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास कर रहा है। दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर स्थित जैन समुदाय के पवित्र स्मारक 'मान स्तंभ' के उद्घाटन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। उनका आरोप था कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह लड़ाई केवल किसी एक दल के समर्थकों की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की है।

उन्होंने कहा कि चाहे नाम तृणमूल कांग्रेस,भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) या कांग्रेस के समर्थकों के हों, किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों से खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि वह न्याय की प्रार्थना कर रही हैं और लोगों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने की अपील करती हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर को 'मिनी भारत' बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग पीढ़ियों से सौहार्दपूर्वक रहते आए हैं। दुर्गा पूजा,क्रिसमस और ईद जैसे सभी पर्वों में हर समुदाय की भागीदारी इस क्षेत्र की परंपरा और संस्कृति को दर्शाती है।

कृषि मंत्री की दो टूक...किसानों का पैसा रोकने पर लगेगा 12% ब्याज,2 लाख करोड़ की खाद सब्सिडी सीधे खाते में

नई दिल्ली,25 फरवरी 2026। केंद्र सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए कड़े और पारदर्शी सुधारों की बात कही गई है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा कोई भी समझौता या लेटलतीफी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भुगतान में देरी पर जुर्माना और डीबीटी पर जोर

किसानों के बकाये को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कृषि मंत्री ने चेतावनी दी कि जो भी एजेंसी या राज्य सरकार किसानों का पैसा रोकेगी, उसे उस राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय देरी को खत्म करने के लिए अपना हिस्सा सीधे किसानों के खातों में भेजने के

विकल्प पर काम कर रही है। इसके अलावा, एक बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत देते हुए उन्होंने सालाना 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद (उर्वरक) सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजने पर विचार करने की बात कही, ताकि वास्तविक अन्नदाता को इसका सीधा फायदा मिल सके। किसानों को फसल का तुरंत दाम दिलाने के उद्देश्य से श्री चौहान ने सुझाव दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की प्रक्रिया मौजूदा तीन महीने के बजाय अधिकतम एक महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।

महाराष्ट्र में सात राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव..

5 मार्च तक नामांकन

16 मार्च को होगा मतदान

नई दिल्ली,25 फरवरी 2026। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है,क्योंकि राज्य से सात राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई है। सदस्यों के चुनाव के लिए 16 मार्च को होगा। इस बात की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर विलास अठवाले ने दी। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 मार्च है। इसके बाद 6 मार्च को नामांकनों की जांच (स्क्रूटनी) होगी और 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य इस चुनाव में मतदान करेंगे।

ओडिशा माइनिंग अफसर के घर से 4.27 करोड़ नकद मिले

नोट गिनने की मशीनें लाना पड़ीं,30 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था

कटक,25 फरवरी 2026। ओडिशा विजिलेंस ने बुधवार को कटक सर्किल के डिप्टी डायरेक्ट (माइंस) देबब्रत मोहंती के घर से 4.27 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। मोहंती को लाइसेंसी कोयला व्यापारी से 30 हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरोप है कि वह कोयला डिपो को बिना रुकावट चलाने और काम आसान करने के बदले रिश्वत ले रहा था। यह ट्रैप ऑपरेशन ओडिशा विजिलेंस ने रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने के बाद किया था। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस की टीमों ने मोहंती और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर छापे मारे। विभाग ने मठासाही में मोहंती के पैतृक घर और भुवनेश्वर के पाटिया इलाके वाले फ्लैट पर छापा मारा।

भुवनेश्वर वाले फ्लैट से सूटकेस, ट्रॉली बैग और अलमारियों में नोटों के ढेर मिले। इसके अलावा, उसके ऑफिस से 1.20 लाख नकद भी बरामद हुए।

नोटों की गिनती के लिए करेंसी काउंटिंग मशीनें लाई गईं। विजिलेंस के भुवनेश्वर डिवीजन के एसपी सरोज कुमार समल ने बताया कि अब तक 4.27 करोड़ की गिनती हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि मोहंती के पास भुवनेश्वर में दो मंजिला मकान है। इसके अलावा अफसर के नाम करीब 130 ग्राम सोना और 2400 वर्गफीट का प्लॉट है, जिस पर दो मंजिला बिल्डिंग बन रही है। मोहंती के नाम 10 बैंक खाते और लॉकर भी हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के बुलढाणा स्थित शेगांव में 'राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026' का उद्घाटन किया

आयुष प्रणालियां समग्र कल्याण के लिए एक व्यापक जीवनशैली ढांचा प्रदान करती हैं : राष्ट्रपति मुर्मु

नई दिल्ली,25 फरवरी 2026। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में 'राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026' का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस के सहयोग से आयोजित यह चार दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं,शोधकर्ताओं,चिकित्सकों, किसानों,उद्योग प्रतिनिधियों और नागरिकों को एक साझा मंच पर लाया है। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि संत श्री गजानन महाराज की पावन धरा पर उपस्थित होकर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में आने से पहले उन्हें उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला। उन्होंने याद किया कि संत गजानन महाराज ने अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और सभी जीवों के लिए करुणा और

समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को समर्पित कार्यक्रम का उद्घाटन करना बड़े संतोष का विषय है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी परंपरा में कहा गया है, 'आरोग्यम परमम सुखम ', जिसका अर्थ है कि अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक स्वस्थ शरीर सभी कर्तव्यों के पालन के लिए प्राथमिक साधन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को मजबूत करने में स्वस्थ नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रेखांकित किया कि आयुर्वेद,योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी ने निवारक, संवर्धक और उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल में अमूल्य योगदान दिया है और समाज का संतुलित जीवन की ओर मार्गदर्शन करना जारी रखा है। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि दुनिया तेजी से इस बात को स्वीकार कर रही है कि वास्तविक कल्याण के लिए शरीर और मन के बीच सामंजस्य आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आयुष प्रणालियां केवल उपचार ही नहीं, बल्कि संतुलित आहार,दैनिक और मौसमी दिनचर्या,योग,ध्यान और प्राकृतिक उपचारों पर आधारित एक व्यापक जीवनशैली ढांचा प्रदान करती हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीमारियों का बोझ कम करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए निवारक और समग्र स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक है। राष्ट्रपति ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत औषधीय पौधों और पारंपरिक ज्ञान की समृद्ध विरासत का धनी है। औषधीय पौधों के संरक्षण और वैज्ञानिक खेती के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि कच्चे माल के आधार को मजबूत करने से सतत स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी।

मैं राहुल गांधी को बेनकाब करना चाहता हूं,उनके पाकिस्तान समर्थकों से संबंध : नितिन नबीन

नई दिल्ली, 25 फरवरी 2026। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किए बिना विदेश यात्राएं करने और भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक तत्वों से करीबी संबंध रखने का आरोप लगाया। नबीन ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक समझौते वाले मिशन पर होने का आरोप लगाया,जिसकी शुरुआत उनके परदादा और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी और जो पीढ़ियों से जारी है। भाजपा अध्यक्ष की ये टिप्पणियां पिछले सप्ताह दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा 'पीएम समझौता कर चुके हैं' के नारे के साथ किए गए शर्टलेस विरोध प्रदर्शन को लेकर उठे विवाद के बीच आई हैं। यह नारा अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते की ओर इशारा था। एक महीने पहले भाजपा अध्यक्ष बने 45 वर्षीय नितिन नबीन ने पत्रकारों से कहा, आज मैं नेहरू-गांधी परिवार

के उस समझौते वाले मिशन को उजागर करना चाहता हूं, जिसने निजी लाभ के लिए राष्ट्रीय हितों का सौदा कर लिया है। मैं राहुल गांधी को बेनकाब करना चाहता हूं, जो एक बब्बर शेर की तरह इतरा रहे हैं। नबीन ने नेहरू द्वारा कथित तौर पर देश की बढ़ती आबादी को बोझ बताने और 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में मिली हार का मुद्दा उठाया और इंदिरा गांधी पर 1971 में पाकिस्तान को हराने के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को छोड़ देने का आरोप लगाते हुए इसे समझौतावादी मिशन के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।

संपादकीय

एआई को समावेशी बना रहा भारत

भारत एआई इंपैक्ट समिट ने एआई पर वैश्विक विमर्श को नई दिशा दी, जिसमें भारत ने समावेशी और अवसर-केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। पश्चिमी देशों की सुरक्षा चिंताओं के विपरीत,भारत ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्टक्चर के साथ एआई के उपयोग पर जोर दिया...

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट मात्र एक शिखर सम्मेलन न होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर वैश्विक विमर्श को दिशा देने वाला अहम पड़ाव बना। यह सम्मेलन एआई के मोर्चे पर आकार ले रहे भौगोलिक,राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के मंच के रूप में भी उभरा। हाल के दौर में एआई सम्मेलनों के केंद्र में सुरक्षा,अस्तित्व संबंधी जोखिम और नियमन की चिंता जैसे मुद्दे ही छाए रहे। ब्रिटेन में आयोजित ऐसे पहले प्रमुख सम्मेलन को जहां एआई सुरक्षा समिट का नाम दिया गया तो नई दिल्ली में इसके नामकरण में प्रभाव शब्द का समावेश हुआ। यह भी भारत की बड़ी उपलब्धि रही,क्योंकि प्रभाव का अर्थ बहुत व्यापक है। यानी यह तकनीक कैसे अपनी उपयोगिता से प्रभावित कर सकती है और इस तक सबकी समावेशी पहुंच कैसे सुनिश्चित हो।

कई दिग्गज संस्थाओं के सर्वेक्षणों में यह सामने आया है कि भारत और चीन जैसे देशों में एआई के प्रति 88 प्रतिशत तक की सकारात्मक भावना है। इसके उलट पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसे लेकर सतर्कता एवं संदेह का भाव दिखता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एआई ने कुछ स्थापित पारंपरिक पेशों के लिए खतरे की घंटी बजाई है तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इसे अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यथार्थ ही कहा है कि कुछ पक्ष एआई में डर देखते हैं तो भारत इसमें अपना भविष्य देखता है। एआई से जुड़ी भारत की उम्मीदें उसके अनुभवों से ही उपजी हैं। जैसे आधार और यूपीआइ जैसे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ने भुगतान,पहचान सत्यापन और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में तमाम बाधाओं को दूर करते हुए दैनिक जीवन को बहुत सुगम बनाया है।

यह इसका जीवंत प्रमाण है कि कोई तकनीक कैसे लागत को घटाकर सक्षमता को बढ़ा सकती है। स्वाभाविक है कि भारत अपनी इस सफलता को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है। इसी क्रम में उसने एआई समिट में स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शासन में समावेशन को बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की एआई के साथ जुगलबंदी का खाका पेश किया।

पिछले एआई सम्मेलनों में विमर्श का केंद्रबिंदु सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताएं रहीं,जबकि नई दिल्ली घोषणापत्र मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर,सस्ती कनेक्टिविटी और कार्यबल प्रशिक्षण पर जोर देता है। इसमें यह स्वीकार्यता प्रदान की गई है कि सार्थक एआई भागीदारी के लिए कंप्यूटिंग शक्ति,इंटरनेट पहुंच और कुशल लोगों की आवश्यकता होती है।

यह उचित स्थानों पर ओपन-सोर्स एआई का समर्थन भी करता है। इसके पीछे यही सोच रहा कि कई देश अपने तंत्र को शून्य से खड़ा करने की स्थिति में नहीं तो उनके लिए कुछ गुंजाइश तो मिलनी ही चाहिए। निःसंदेह एआई से जुड़े अपने जोखिम भी हैं,पर भारत ने अपने दृष्टिकोण में उसकी व्यावहारिक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया है।

सहभागिता एवं स्वीकार्यता की दृष्टि से भी सम्मेलन सफल रहा। विभाजित भू-राजनीतिक माहौल में भी नई दिल्ली घोषणापत्र पर 80 से अधिक देशों एवं वैश्विक संगठनों के हस्ताक्षर इसकी सफलता को रेखांकित करते हैं। यह सही है कि जिन घोषणाओं पर सहमति बनी,वे बाध्यकारी नहीं हैं, किंतु याद रहे कि किसी भी व्यवस्था के आकार लेने में उस पर सहमति बनना आवश्यक होता है। उसके बाद ही कानूनी ढांचा आकार लेता है।

आर्थिक पहलुओं पर भी प्रगति देखने को मिली है। इसमें 400 अरब डालर से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं। इनमें 250 अरब डॉलर का निवेश बुनियादी ढांचा संबंधी आवश्यकताओं तो 150 अरब डॉलर गहन तकनीकी पूंजी से जुड़ा होगा। एआई कंप्यूटिंग क्षमता, डाटा केंद्रों, सेमीकंडक्टर्स और पावर सिस्टम की आवश्यकता किसी से छिपी नहीं है। इस क्रम में भारत ने इस वर्ष के अंत तक एक लाख जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) की दिशा में कदम बढ़ाकर विस्तारित इंडिया एआई मिशन के तहत योजनाओं की घोषणा करके अपनी गंभीरता का संकेत दिया। कंप्यूटिंग के दम पर ही एआई का अपना इकोसिस्टम विकसित हो सकता है। अन्यथा सभी बातें सैद्धांतिक बनकर रह जाती हैं।

एक और महत्वपूर्ण योगदान मानव(एमएएनएवी) का उल्लेख रहा। इसका अर्थ है नैतिक प्रणाली,उत्तरदायी शासन,राष्ट्रीय संप्रभुता,सुलभ एआई और वैध प्रणाली। यह मानव-केंद्रित दृष्टिकोण आशावाद और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यह इस पर बल देता है कि एआई प्रणालियां विधिसम्मत,लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप एवं व्याख्या की दृष्टि से सरल होनी चाहिए।

सम्मेलन ने कुछ स्वैच्छिक रूपरेखाएं भी निर्धारित की गई हैं। जैसे एआई के लोकतांत्रिक प्रसार के लिए एक चार्टर,सफल प्रयोगों को अपनाने के लिए विश्वसनीय तौर-तरीके एवं मानक। ऐसी पहल उन संस्थागत ढांचे की नींव रखती है जो समय के साथ और परिपक्व हो सकता है। ध्यान रखना होगा कि जो देश इसके मानदंडों को आकार देंगे, वही लाभ और जोखिमों को भी तय करेंगे। इस दिशा में यदि एआई कुछ कंपनियों या देशों में केंद्रित रहती है तो असमानता बढ़ सकती है। यदि यह सुलभ बुनियादी ढांचा बनती है,तो अवसरों का विस्तार हो सकता है।

शिखर सम्मेलन की सफलता तीन क्षेत्रों में निहित है। पहला,इसने एआई के मोर्चे पर अब तक का सबसे व्यापक गठबंधन तैयार किया। दूसरा, इसने नीतिगत महत्वाकांक्षा को ठोस निवेश प्रतिबद्धताओं के साथ समन्वित किया। तीसरा,इसने ऐसा नैरेटिव प्रस्तुत किया जो एक दूसरे को विरोध में खड़ा करने के बजाय नवाचार को समावेशन के साथ जोड़ता है।

इस संदर्भ में अब भविष्य की चुनौती यही है कि नवाचार की तेजी को बनाए रखते हुए सशक्त जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। यदि भारत इस संतुलन को कायम रख पाता है तो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 को उस क्षण के रूप में याद किया जा सकता है जब वैश्विक एआई शासन-संचालन का केंद्रबिंदु व्यापक भागीदारी की ओर स्थानांतरित होना प्रारंभ हुआ।

शिक्षा को हिंसक नहीं,संवेदनशील बनाना होगा

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं,बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा सकती है। यह चिंता केवल अच्छे अंक लाने की नहीं,बल्कि अपेक्षाओं के बोझ को ढोने की है। दुर्भाग्य यह है कि यह दबाव कई बार इतना असहनीय हो जाता है कि वह आत्मघाती या हिंसक रूप ले लेता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंके एक भयावह सच उजागर करते हैं। वर्ष 2013 से 2023 के बीच छात्रों की आत्महत्या की दर में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह केवल आंकड़ा नहीं,बल्कि हजारों परिवारों के टूटने की कहानी है। इन आत्महत्याओं के पीछे पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक अपेक्षाएं,सामाजिक तुलना और आर्थिक तनाव प्रमुख कारण बताए जाते हैं। लेकिन हाल में लखनऊ में जो घटना सामने आई, उसने इस संकट को एक और खतरनाक दिशा में मोड़ दिया है। लखनऊ की घटना केवल परीक्षा दबाव की कहानी नहीं है,बल्कि परिवारों में बढ़ती संवेदनहीनता,संवादहीनता और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा का दर्पण है। पुलिस जांच के अनुसार एक पैथोलॉजी लैब संचालक पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे और उस पर नीट जैसी परीक्षा पास करने का लगातार दबाव बना रहे थे। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच बहस हुई और 21 वर्षीय युवक ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपराध छिपाने के लिए शव के टुकड़े किए,कुछ बाहर फेंके,कुछ घर में छिपाए,छोटी बहन को धमकाया और पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले लापता होने और फिर आत्महत्या की कहानी गढ़ी। यह सब बताता है कि यह क्षणिक आवेश नहीं था,बल्कि भीतर लंबे समय से पल रही कुंठा,आक्रोश और मानसिक विघटन का परिणाम था। प्रश्न यह है कि एक बेटे के भीतर इतनी नफरत कैसे पनप सकती है? क्या 'कुछ बनने' का दबाव इतना भारी हो सकता है कि वह रिश्तों को भी तार-तार कर दे? हर माता-पिता चाहते हैं कि उनकी संतान सफल हो,प्रतिष्ठित करियर बनाए, समाज में सम्मान पाए। लेकिन जब यह चाहत संवाद और सहयोग की जगह नियंत्रण और दबाव का रूप ले लेती है, तब वह प्रेरणा नहीं, मानसिक उत्पीड़न बन जाती है। जब शिक्षा जीवन-निर्माण का माध्यम न होकर,विनाश का कारण बन जाती है।

भारत में नीट और जी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं के लिए उम्मीद का प्रतीक हैं। नीट में पिछले वर्ष 23 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया, जबकि ज्वाइंट एन्टरेंस एक्जामिनेशन (जेईई) के एक सत्र में 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया। इन लाखों विद्यार्थियों में से केवल कुछ हजार ही शीर्ष संस्थानों तक पहुंच पाते हैं। शेष विद्यार्थियों के हिस्से अक्सर निराशा, आत्मग्लानि और सामाजिक तुलना का दंश आता है। जब सफलता का पैमाना केवल रैंक और अंक बन जाए,तो असफलता जीवन का अंत प्रतीत होने लगती है। कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों में हर वर्ष आत्महत्या की खबरें सामने आती हैं। कोटा देश की कोचिंग राजधानी कही जाती है,जहां हजारों छात्र सपने लेकर पहुंचते हैं। लेकिन उन्हीं सपनों का बोझ कई बार उनके जीवन से भारी पड़ जाता है। यह केवल व्यक्तिगत कमजोरी का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का परिणाम है जिसमें प्रतियोगिता सहयोग से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। लखनऊ की घटना में एक और तथ्य उल्लेखनीय है-आरोपी छात्र की मां का निधन हो चुका था। घर में चाचा-चाची मौजूद थे,लेकिन क्या उस युवक की मनःस्थिति को समझने का प्रयास किया गया? क्या उसके भीतर के तनाव, अकेलेपन और भय को किसी ने सुना? यदि परिवार में नियमित संवाद होता, यदि मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लिया जाता जितनी अंकों को, तो शायद यह भयावह वारदात टाली जा सकती थी। आज समस्या केवल आत्महत्या तक सीमित नहीं है। बच्चे हिंसक भी हो रहे हैं। यह हिंसा बाहरी नहीं, भीतर से उपज रही है-कुंठा, अपमानबोध,तुलना और असफलता के भय से। जब बच्चे को यह महसूस होने लगे कि वह केवल एक 'प्रोजेक्ट' है, एक 'इन्वेस्टमेंट' है, जिसे किसी निश्चित पेशे में ढालना है, तब उसकी स्वतंत्र पहचान कुचल जाती है। वह या तो भीतर ही भीतर टूट जाता है या विस्फोट कर देता है। शिक्षा का उद्देश्य जीवनदायिनी होना चाहिए-विवेक, संवेदना और आत्मविश्वास का विकास करना चाहिए। लेकिन जब शिक्षा केवल प्रतिस्पर्धा और रैंकिंग का माध्यम बन जाए, तो वह तनाव और हिंसा को जन्म देती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता,और न ही बनना चाहिए। विविध प्रतिभाओं को सम्मान देने वाली सामाजिक मानसिकता विकसित किए बिना यह संकट कम नहीं होगा। इस संदर्भ में तीन स्तरों पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। पहला,परिवार। माता-पिता को यह समझना होगा कि अपेक्षा और दबाव में अंतर है। अपेक्षा प्रेरणा देती है,दबाव भय पैदा करता है। बच्चों के साथ खुला संवाद, उनकी रुचियों को समझना,असफलता को स्वीकार्य बनाना और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। 'तुम्हें डॉक्टर बनना ही है' की जगह 'तुम जो बनना चाहो, हम साथ हैं' जैसी सोच विकसित करनी होगी। दूसरा, शिक्षा संस्थान। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को केवल परिणाम देने वाली मशीन नहीं, बल्कि संवेदनशील संस्थान बनना होगा। नियमित काउंसलिंग, तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं और परीक्षा को जीवन-मरण का प्रश्न न बनाने की संस्कृति विकसित करनी होगी। शिक्षकों को भी विद्यार्थियों की मानसिक दशा पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तीसरा, सरकार और समाज। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और कलंकमुक्त बनाना होगा। परीक्षा प्रणाली में सुधार, वैकल्पिक करियर मार्गों को बे ावा, और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देना समय की मांग है। मीडिया को भी सनसनी की बजाय संवेदनशील रिपोर्टिंग करनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन घटनाओं को सामान्य न मानें। हर आत्महत्या और हर हिंसक घटना हमारे सामाजिक ताने-बाने में दरार का संकेत है। यदि हम इसे केवल 'व्यक्तिगत मामला' कहकर टाल देंगे, तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। लखनऊ की घटना हमें झकझोरती है। यह बताती है कि शिक्षा का दबाव,पारिवारिक संवादहीनता और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा मिलकर कितनी भयावह परिणति ला सकती है। अब समय है कि हम सामूहिक आत्ममंथन करें। शिक्षा को जीवन का उत्सव बनाएं,न कि भय का कारण। बच्चों को लक्ष्य दें,लेकिन उनके पंख न काटें। सपने दिखाएं,पर उन्हें सांस लेने की जगह भी दें। जब तक हम सफलता की परिभाषा को व्यापक नहीं करेंगे और बच्चों को अंक से अधिक मनुष्य मानना नहीं सीखेंगे,तब तक यह संकट बना रहेगा। परीक्षा का मौसम हर साल आएगा, लेकिन यदि हम संवेदनशील समाज बन सके, तो शायद अगली पीढ़ी के लिए यह मौसम भय का नहीं, आत्मविश्वास का प्रतीक बन सकेगा।

अब आ ही गया होलाष्टक

पूनम शर्मा
पटना,बिहार

होलाष्टक होली के ठीक 8 दिन पहले से शुरू होने वाली अवधि को सामान्य भाषा में हम होलाष्टक कहते हैं।

यह होली से पहले 8 दिनों तक चलता है इस बीच किसी भी प्रकार का शुभ काम किसी काम की शुरुआत या किसी भी मांगलिक कार्य के अनुष्ठान के लिए वर्जित माना जाता है। पारंपरिक मानता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम सीमा पर होती हैं।

हमारे धर्म के सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर चीज के प्रमाण मौजूद हैं हमारे धर्म में बस जाने और समझने की आवश्यकता है।

इस वर्ष 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक रहेगा 3 मार्च को होलिका दहन के साथ होलाष्टक की नकारात्मक ऊर्जाएं जलकर होलिका दहन में समाप्त हो जाएंगी। होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा यानी की होलिका दहन के दिन समाप्त हो जाता है।

यह वक्त किसी नई शुरुआत के लिए अच्छा नहीं माना जाता जबकि आध्यात्मिक साधना मंत्र उच्चारण दान ध्यान जैसे कार्यों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस समय किसी भी साधना को करने का फल बेहतर प्राप्त होता है। ध्यान रहे किसी का अहित करने की मंशा लेकर किया गया कोई भी अनुष्ठान कोई भी मंत्र उच्चारण कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। यहाँ पर तो होलिका को मिले हुए वरदान के बाद भी होलाष्टक के अंत होते-होते तक होलिका का अंत हो गया था। हमारा धर्म असंख्य उदाहरण से भरा हुआ है कि किसी का अहित चाहने वाले का सर्वस्व स्वाहा हो जाता है।

भक्त प्रहलाद की कथा :- मान्यता है कि भक्त प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे उनकी यह भक्ति हिरण्यकश्यप जो की प्रहलाद के पिता थे उन्हें तनिक भी पसंद नहीं आती थी। क्योंकि अपने राज्य में वह अपने आप को भगवान मानकर अपनी पूजा करने के लिए प्रजाजन को मध्य करता था। सिर्फ इसी कारण अपने ही पुत्र को 8 दिनों तक प्रताड़ित किया था हिरण्यकश्यप ने। कभी उन्हें पहाड़ से नीचे फिकवाया , तो कभी हाथी के पैरों के नीचे रौदने की कोशिश की । जब हर तरीके से हार गया तो अपनी बहन होलिका की मदद से अग्नि के द्वारा भक्त प्रहलाद को जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा था हिरण्यकश्यप और होलिका ने पर भगवान विष्णु के भक्ति का कुछ भी अहित न कर सके और उल्टा वरदान मिलने के बाद भी होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई।

कामदेव की कथा:- एक मान्यता यह भी है की भगवान शिव ने इन्हीं दोनों कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था जिससे कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया था और एक संतुलन उत्पन्न हो गया था।

होलाष्टक से लेकर होलिका दहन तक का समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रबल समय होता है। परंतु होलिका दहन के साथ समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं जलकर स्वाहा हो जाती हैं। जो कि हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का महत्व समझ कर चली जाती है।

किसी का अहित करने की मंशा कुछ दिनों तक भले ही आपको सुख महसूस करवाएं लेकिन यकीन मानिए कुछ ही दिनों के बाद होलिका दहन जैसी ही कोई ना कोई नियति आती है और सारे अहम का नाश करके एक नई शुरुआत की वजह दे जाती है। फाल्गुन मास मैं पेड़ों से पुराने पत्ते टूट कर झड़ जाते हैं और नई खोपले अपना स्वरूप दिखाने लगते हैं। यह प्राकृतिक तौर पर भी एक नई शुरुआत का समय होता है बदलते मौसम के साथ-साथ प्रकृति भी मानो अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रही होती है।

अक्सर हमारी जिंदगी में...

प्रोफेसर शाम लाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

अक्सर हमारी जिंदगी में
वह नहीं होता जो हम चाहते हैं!
अक्सर हमारी जिंदगी में
सब हमारे वफादार नहीं होते!
अक्सर हमारी जिंदगी में
कोई ना कोई मददगार होता है!
अक्सर हमारी जिंदगी में
कोई ना कोई भरोसा तोड़ता है!
अक्सर हमारी जिंदगी में
मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है!
अक्सर हमारी जिंदगी में
सब कुछ पाकर भी संतोष नहीं होता!
अक्सर हमारी जिंदगी में
हमें पारिवारिक सुख नहीं मिलता!
अक्सर हमारी जिंदगी में
भलाई करके भी हमें शिकायत मिलती है!
अक्सर हमारी जिंदगी में
छोटे लोग ही हम पर एहसान कर जाते हैं!
अक्सर हमारी जिंदगी में
चापलूसी करने वाले ही धोखा देते हैं!

मैं ठीक हूं...

केशी गुप्ता
द्वारका,नई दिल्ली

मैं ठीक हूं अक्सर हर ज़बान
पर होता है ये
मैं भी अक्सर पूछे जाने पर
कहती रहती हूं ये
जब भी कोई हाल पूछता है मुझसे मेरा
इस एक वाक्य में सब छुपा लेती हूं मैं
दिल में कई अनकहे द्वंद्व चल रहे होते हैं
जो भीतर ही भीतर जख्म दे रहे होते हैं
खुद ही मरहम पट्टी उनकी कर देती हूं मैं
हर चीख को अपने अंदर दबा लेती हूं मैं
मैं ठीक हूं कहने की इस इक आदत ने
हमको गिर गिर कर
संभालना सिखा दिया
इसको हमने अपने
जीने का अंदाज़ बना लिया
जीना है मुस्कुराते हुए
दामन में चाहे हों कांटे
फूलों की तरह महकाना है
धूप छांव में रहना है
मैं ठीक हूं आज,
बाहर से सब रिश्ता टूट गया
सिर्फ जुबान पर नहीं अब ये कहने को
भीतर से सब ठीक हो गया

दूर किए जाएं माओवाद के उभार के कारण

आर के विज

कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माओवादी) अब बिखरने की कगार पर है। यह संगठन 2012 से ही दंडकारण्य में लगातार कमजोर हो रहा था, लेकिन कुछ समय पहले उसे तगड़ा झटका लगा। अपनी कार्यनीति में बदलाव कर अगस्त 2024 से माओवादियों ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। जैसे-जैसे सुरक्षा बलों ने उनके इलाकों में सुरक्षा कैंप बढ़ाने शुरू किए,वैसे-वैसे माओवादियों को आश्रय लेने एवं विचरण करने वाले स्थलों को छोड़ना पड़ा।

मई 2025 में माओवादी पार्टी के महासचिव बसवराजू के मारे जाने और अक्टूबर 2025 में पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल उर्फ सोनू एवं केंद्रीय कमेटी सदस्य रूपेश द्वारा करीब 260 साथियों के साथ समर्पण करने के बाद संगठन लगभग बिखर गया। इनमें उत्तर बस्तर, पूर्व बस्तर,गढ़चिरौली और अबूझमाड़ के माओवादी थे। उनके समर्थन में गरियाबंद-धमतरी के माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और दिसंबर में महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ स्पेशल जोन के प्रभारी रामदेर और सचिव कबीर ने भी अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया।लंबे समय तक मिलिट्री बटालियन का कमांडर रहा हिड़मा माडवी आंध्र में एक मुठभेड़ में मारा गया। अभी गत दिवस केंद्रीय कमेटी के देवजी और संग्राम ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। माओवादियों की खस्ता हालत देखकर लगता नहीं कि सशस्त्र आंदोलन के पुनर्जीवित होने के कोई आसार हैं। इसलिए जरूरी है कि जहां आंदोलन खत्म हो गया या दक्षिण-पश्चिम बस्तर जहां आंदोलन काफी कमजोर है, वहां सरकार को उस खालीपन को विकास से भरने की जरूरत है, जहां माओवादी विकास में अवरोध बने हुए थे।केंद्र और राज्य की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास की नीतियों के तहत राज्य सरकारें आत्मसमर्पित माओवादियों को आवश्यक लाभ देकर उनके पुनर्वास की कार्रवाई कर रही है। सरकार की नीतियों में विश्वास कायम रखने के लिए यह जरूरी भी है, परंतु यह भी आवश्यक है कि उन सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर किया जाए,जिनके कारण माओवादियों ने ग्रामीणों को अपने पक्ष में कर लिया था। इनमें से सबसे जरूरी है दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता।बस्तर क्षेत्र में बहुत से आदिवासी आयरन की कमी ग्रस्त हैं और उन्हें समय पर दवाई नहीं मिल पाती। उन्हें पीने का साफ पानी भी नहीं मिलता। इसलिए जरूरी है कि ग्रामीणों के बीच मोबाइल एंबुलेंस चला कर दवाइयों का वितरण किया जाए। चूंकि अंदरूनी इलाकों में कई सुरक्षा कैंप स्थापित हैं, इसलिए प्रारंभ में इन कैंपों से ही स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जाएं।

अवैध कब्जे का निस्तारण,हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

स्वराज श्रीवास्तव

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को हटाने को न्यायसंगत बताया, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पात्र लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पुनर्वास और छह महीने तक भत्ता देने का सुझाव दिया।

लंबे समय से विवाद और तनाव के केंद्र में रहे उत्तराखंड के हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे और साथ ही राज्य सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से बसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने वहां से हटाने का फैसला करके वही किया, जो न्यायसंगत था। यदि यह मांग मान ली जाती कि अतिक्रमण करके बसे लोगों को वहीं रहने दिया जाए तो इससे न केवल करीब 30 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा वैध हो जाता, बल्कि रेलवे के विस्तार की महत्वाकांक्षी परियोजना पर ग्रहण भी लगता।

सुप्रीम कोर्ट ने यह सही कहा कि अवैध तरीके से बसे लोग यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे रेल लाइन विस्तार के लिए अन्य विकल्प चुने, लेकिन इसी के साथ उसने इस जमीन से बेदखल होने वालों के प्रति जो मानवीय दृष्टिकोण

अपनाया,उसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग पांच हजार परिवारों के जो हजारों लोग रेलवे और उसके पास की राज्य सरकार की जमीनों पर रह रहे हैं, उनमें से पात्र लोगों को पीएम आवास योजना के तहत आवास दिए जाएं।

इस फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने पात्र परिवारों को विस्थापन के बाद छह महीने तक प्रति माह 2,000 रुपये भत्ता देने का भी वादा किया। पहली नजर में यह लग सकता है कि एक तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को पुरस्कृत किया जा रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस कब्जे को लेकर न तो रेलवे समय रहते चेता और न ही उत्तराखंड सरकार।

यह एक तथ्य है कि आम तौर पर सरकारी विभाग अपनी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर उदासीन बने रहते हैं और फिर यकायक अपनी जमीन खाली कराने की सुध लेते हैं। इससे वहां रह रहे लोगों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। उनके रहने का ठिकाना छिनने के साथ ही उनकी रोजी-रोटी भी प्रभावित होती है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले को नजीर न माना जाए और उसने जो मानवीय दृष्टिकोण अपनाया,वह मदद ज्यादा और अधिकार कम है। देश में हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हैं। इसके लिए कब्जा करने वालों के साथ वे विभाग भी जिम्मेदार हैं,जो अपनी जमीनों पर कब्जे के समय आंखें मूंदे रहते हैं। यदि सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना है तो वहां दशकों से रह रहे लोगों के पुनर्वास के बारे में कोई ठोस नीति बनानी होगी।

ध्यान रहे अपने देश में अपनी ही जमीनों पर बसे लोगों को जब किसी परियोजना के चलते विस्थापित किया गया तो उनमें से भी अनेक का न तो ढंग से पुनर्वास किया गया और न ही उनकी आजीविका की चिंता की गई। निःसंदेह सरकारी अथवा गैर-सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे मुक्त होने चाहिए,लेकिन मानवीय दृष्टिकोण के साथ।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

दूषित पेयजल को लेकर कांग्रेस ने निगम कार्यालय का किया घेराव

पीलिया से दो मौत का आरोप...उच्च स्तरीय जांच की मांग...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति और पीलिया के बढ़ते मामलों को लेकर बुधवार दोपहर कांग्रेसियों ने गौरव पथ स्थित नगर निगम के नए कार्यालय का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद और जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन,जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शन से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता कोठीघर से रैली निकालकर निगम कार्यालय पहुंचे। पूर्व सूचना के चलते पुलिस और प्रशासन ने बैरिकेडिंग की थी,जिसे हटाकर कार्यकर्ता परिसर में प्रवेश कर गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहर के कई वार्डों में दूषित पानी की सप्लाई से 4 दर्जन से अधिक लोग पीलिया से पीड़ित हैं। उनका आरोप है कि सतीपारा के 13 वर्षीय बालक और झंझटपारा निवासी एक व्यक्ति की मौत दूषित पानी पीने से हुई है। नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि पीलिया प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान महापौर द्वारा दिया गया बयान गैरजिम्मेदाराना है। उनका कहना था कि सूचना समय पर नहीं दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि सूचना मिलने के बावजूद निगम प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की।

100 सैंपल में एक ही पॉजिटिव : इधर,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. प्रेम सिंह मार्को ने पीलिया के मोमिनपुरा के अलावा अन्य क्षेत्रों में फैलने की बात से इंकार किया है। उन्होंने बताया कि अब तक केवल मोमिनपुरा क्षेत्र में ही पीलिया के मरीज मिले हैं। अन्य वार्डों में मितानिनों के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। हाल ही में लिए गए 100 ब्लड सैंपलों में से केवल 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएमएचओ के अनुसार फिलहाल स्थिति सामान्य है।

दोनों मौतें पीलिया से प्रमाणित नहीं : सीएमएचओ डॉ. मार्को ने बताया कि 13 वर्षीय बालक की मेडिकल कॉलेज अस्पताल से रिपोर्ट मंगाई गई थी। वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुसार बालक को मस्तिष्क ज्वर (ब्रेन फीवर) था, जिसके कारण उसे रेफर किया गया था। वहीं दूसरे मृतक की जांच रिपोर्ट भी संबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर से मंगाकर देखी गई। रिपोर्ट में पीलिया की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों की मौत पीलिया से होने की पुष्टि जांच रिपोर्ट के आधार पर नहीं की जा सकती। एक ओर कांग्रेस उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। मामले को लेकर शहर में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बयानबाजी तेज हो गई है।

भारत मंडपम में युवा कांग्रेस के अमर्यादित प्रदर्शन के विरोध में घड़ी चौक पर उग्र प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी सरगुजा महिला मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर जताया आक्रोश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

एआई समिट के दौरान भारत मंडपम,नई दिल्ली में युवा कांग्रेस द्वारा किए गए अमर्यादित,अभद्र एवं अर्धनग्न प्रदर्शन के विरोध में आज स्थानीय घड़ी चौक अंबिकापुर में भाजपा सरगुजा महिला मोर्चा द्वारा तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया। महापौर मंजूषा भगत एवं प्रदेश महिला मोर्चा महामंत्री फूलेश्वरी सिंह की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़े के नेतृत्व में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। इस अवसर पर शुभांगी बिहाड़े ने तीखा वक्तव्य देते हुए कहा कि एआई समिट जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार का अर्धनग्न और अभद्र प्रदर्शन न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, बल्कि देश की गरिमा और संस्कृति पर सीधा आघात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अराजकता की राजनीति कर रहे हैं और यह कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन अशोभनीय और अमर्यादित आचरण को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की राजनीति से देश की छवि धूमिल होती है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है। भाजपा महिला मोर्चा इस तरह की मानसिकता और राजनीति का कड़ा विरोध करता है। विरोध प्रदर्शन में जिला महामंत्री अरुणा सिंह, मधु चौदाहा, माया मिश्रा, सावित्री जायसवाल, प्रिया सिंह, निशांत सिंह सोलू, आनंदी बड़ा, गुंजन सिंह देव, सरिता मिश्रा, अल्पना मिश्रा, महामंत्री नीलू गुप्ता, प्रियंका चौबे, शालिनी सिंह, सरस्वती यादव, हेमलता शर्मा, सरिता जायसवाल, गनेश्वरी चौहान, गीता पांडेय, मीरा जायसवाल, सुषमा जायसवाल, इंदु गुप्ता, संगीता सोनी, रीना भारती, अर्चना सिंह, अनीश सिंह, दिनेश शुक्ला, अनुराग शुक्ला, जातीन परमार, रमन सिंह, अविनाश मंडल, रोहन मंडल, सुधांशु चौबे एवं रवि सहित महिला एवं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज

कुलपति ने किया उद्घाटन, तीन दिन तक होंगी विभिन्न स्पर्धाएं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विद्यार्थियों की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को मल्टीपर्पस इंडोर गांधी स्टेडियम में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन कुलपति प्रो. राजेंद्र लाकपाले ने किया। तीन दिवसीय यह आयोजन 25 से 27 फरवरी तक चलेगा। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ खेलों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, यह गर्व की बात है। खेल गतिविधियां विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ अनुशासन,नेतृत्व क्षमता,आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करती है। कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से परिसर में सकारात्मक ऊर्जा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनता है। बालक वर्ग सिंगल्स में शुभम जायसवाल (बी.फार्मा तृतीय सेमेस्टर) प्रथम,अनमोल बारी (बी.फार्मा पंचम सेमेस्टर) द्वितीय और कार्तिक प्रजापति (फॉरेस्ट्री द्वितीय सेमेस्टर) तृतीय रहे। बालक वर्ग डबल्स में थकेश्वर पैंकरा व सिमांत सिंह प्रथम, नीतेश गुप्ता व सत्यरूपानंद सिंह द्वितीय तथा रूपेश साहा व अनुराग गुप्ता तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग सिंगल्स में शिवानी राजवाड़े (बायोटेक्नोलॉजी द्वितीय सेमेस्टर) प्रथम,सौम्या सिंह (कंप्यूटर साइंस द्वितीय सेमेस्टर) द्वितीय और शालू खान (फॉरेस्ट्री चतुर्थ सेमेस्टर) तृतीय रहीं। बालिका वर्ग डबल्स में शालू खान व हितेश्वरी पैंकरा प्रथम,अनिमा एक्का व होसन्ना किशपोट्टा द्वितीय तथा राशि गुप्ता व अनुष्का दीप गुप्ता तृतीय रहीं। टेबल टेनिस बालिका वर्ग में रीया राजवाड़े प्रथम,राशि गुप्ता द्वितीय और मधुमिता राजवाड़े तृतीय रहीं। बालक वर्ग में अनमोल बारी प्रथम,अजय कुमार साहू द्वितीय तथा सिमांत सिंह तृतीय स्थान पर रहे। इसके अलावा शतरंज,कैरम, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई,जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत 'सियान विवेक युवा आनंद' कार्यक्रम आयोजित, पीढ़ियों के बीच संवाद को मिला बढ़ावा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

समाज कल्याण विभाग,छत्तीसगढ़ द्वारा आज अटल वयो अभ्युदय योजना अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन की दिशा में ठोस पहल करते हुए 'सियान विवेक युवा आनंद' (इंटर जेनरेशनल बॉन्डिंग इवेंट) कार्यक्रम का आयोजन राजमोहिनी भवन में किया गया। कार्यक्रम में चिंतामणि महाराज, सांसद सरगुजा, मंजूषा भगत, महापौर,तथा प्रियंका गुप्ता, एम.आई.सी. सदस्य नगर निगम की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग बच्चों एवं युवाओं की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों का सम्मान एवं संरक्षण,पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करना,पीढ़ियों के बीच संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देना तथा सामाजिक सुरक्षा एवं भावनात्मक लगाव को मजबूत करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही जीवन की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का समाज में बहुमूल्य योगदान है तथा युवाओं को उनके अनुभव,सीख एवं सुझावों का सम्मान करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन से ही समाज और राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम स्थल पर समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के अंतर्गत खेलकूद, परिचर्चा,'पुरखौती किस्सा' कहानी सत्र,पहेली एवं प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गई,जिससे वरिष्ठजनों एवं युवाओं के बीच आत्मीय संवाद स्थापित हुआ।

राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन

प्रधानमंत्री का पुतला फूंका,पुलिस से झूमाझटकी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की अलोकतांत्रिक गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को युवा कांग्रेस सरगुजा ने जिलाध्यक्ष विकल झा के नेतृत्व में घड़ी चौक पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। पुतला दहन के दौरान पुलिस द्वारा बेवजह विवाद एवं दोहरे रवैये के उपरांत युवा कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन का भी पुतला फूंका। कांग्रेस का आरोप है कि एप्सटीन फाइल में मोदी और उनके मंत्री मंडल के सदस्यों और उद्योगपति मित्रों का नाम आने के दबाव और अमेरिका के कोर्ट में फंसे अडानी को बचाने के लिये मोदी सरकार ने ट्रंप के सामने सरेंडर करते हुए देश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाला ट्रेड डील कर लिया है। मोदी सरकार के इस सरेंडर नीति के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन किया था। इस लोकतांत्रिक विरोध से बौखलायी केंद्र सरकार ने युवा कांग्रेस के खिलाफ देश भर में दमन चक्र चलाया हुआ है। युवा कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। इसके विरोध में आज युवा कांग्रेस सरगुजा ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकल झा ने कहा कि कांग्रेस ने अहिंसात्मक ढंग से विरोध प्रदर्शन का अधिकार गांधी जी से सीखा है। एआई समिट में युवा कांग्रेस के बब्बर शेर वही कर रहे थे। लेकिन लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन से अंग्रेज भी डरते थे और अंग्रेजों की चाटूकारिता करने वाली विचारधारा के आज के शासक भी डरते हैं। इसी का परिणाम है कि आज अंग्रेजों के चाटुकार अंग्रेजों का अनुसरण करते हुए लोकतांत्रिक प्रदर्शन का दमन करने में लगे हुए हैं। इस दौरान गुरप्रीत सिद्धू, आलोक सिंह, रजनीश सिंह, नीतीश चौरसिया, उत्तम रजवाड़े, सतीश बारी, विष्णु सिंहदेव, आशीष जायसवाल, आकाश अग्रहरि, विकास केशरी, सतीश घोष, संजर नवाज, भोले रजवाड़े, आकाश यादव, अंकित जायसवाल, ऋषभ जायसवाल, प्रियांशु जायसवाल, दीपेंद्र मंडल, सौरभ मिस्तरी, आयुष सिंह, सुजय मंडल, लोलर सिंह, आदि उपस्थित थे

पुलिस के साथ झूमाझटकी और विवाद : पुतला दहन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। बात एफआईआर करने तक पहुंच गई थी। इस पुतला दहन के कुछ समय पहले भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा बेरोकटोक राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया था, जिसके वीडियो सामने हैं। तब पुलिस मूकदर्शक बनी रही,लेकिन युवा कांग्रेस के पुतला दहन को रोकने के लिए पुलिस ने काफी जद्दोजहद की। इस दोहरे रवैये के कारण कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। बाद में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के हस्तक्षेप से मामला सुलझा।

ब्रेक फेल होने पर ट्रक से कूदे खलासी की सिर में चोट लगने से मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

ब्रेक फेल होने पर खलासी जान बचाने के लिए कूदने की कोशिश की पर उसका शर्ट वाहन के गेट में फंस गया और सडक़ पर सिर के बल जा गिरा। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहां जांच के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना 23 फरवरी को कुसमी थाना क्षेत्र के जामटोली की है। जानकारी के अनुसार चंदीप पाल पिता संयज पाल उम्र 23 वर्ष झारखंड के गढ़वा जिले के सोनबरसा का रहने वाला था। इसका जीजा ट्रक चलाता है। उसी ट्रक में चंदीप खलासी का काम करता था। 23 फरवरी को जीजा-साला सामरी से बॉक्साइड लोड कर गढ़वा मेराल जा रहा था। रास्ते में कुसमी स्थित जामटोली घाट के पास वाहन का ब्रेक फेल हो गया। इस दौरान चंदीप जान बचाने के लिए ट्रक से कूदने की कोशिश की पर उसका शर्ट वाहन के गेट के कुंडी में फंस गया।

मैनपाट में हाथियों का हमला...बुजुर्ग महिला की मौत,लकड़ी लेने गई थी जंगल,सुबह मिला शव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा संभाग में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना मैनपाट क्षेत्र की है, जहां हाथियों ने एक बुजुर्ग महिला को पटककर मार डाला। बुधवार सुबह महिला का शव जंगल में बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार मैनपाट के ग्राम बरिमा के पकरीपारा निवासी 65 वर्षीय महिला मंगलवार को गांव से लगे जंगल में जलावन लकड़ी लेने गई थी। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। बुधवार सुबह जंगल में उसका शव पड़ा मिला। मौके पर हाथियों के पैरों के निशान पाए गए, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हाथियों ने ही उसे कुचल दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद बरिमा गांव में आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर हाथियों की गतिविधियों की समय पर सूचना नहीं देने का आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि हाथियों के गांव के आसपास होने की जानकारी नहीं मिलने से लोग अनजाने में जंगल चले जाते हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मृतका के परिजनों को शीघ्र मुआवजा देने और हाथियों की निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में अतिरिक्त प्लेटफार्म निर्माण मार्च से,फुट ओवर ब्रिज,डिजिटल डिस्प्ले का कार्यादेश जारी,जन औषधि केंद्र को भी मंजूरी

आयोजित 21 वीं बैठक में सरगुजा क्षेत्र से जुड़े रेलवे विकास कार्यों पर विस्तार से की गई चर्चा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य मुकेश तिवारी ने बताया कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में अतिरिक्त प्लेटफार्म निर्माण का कार्य मार्च माह से प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही स्टेशन में 20 फीट चौड़े (6 मीटर) फुट ओवर ब्रिज तथा डिजिटल कोच डिस्प्ले प्रणाली की स्थापना के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन में एक अतिरिक्त मार्ग विकसित करने की संभाव्यता को लेकर परीक्षण कराया जा रहा है। वहीं, अंबिकापुर स्टेशन परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र प्रारंभ करने के लिए रेलवे महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है।

बिलासपुर रेलवे के जोनल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इस बैठक में अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में अतिरिक्त प्लेटफार्म निर्माण की स्वीकृति, टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी होने के बावजूद अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया । इस मुद्दे को उठाते हुए जेडआरयूसीसी सदस्य मुकेश तिवारी ने कहा कि अतिरिक्त प्लेटफार्म की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण ट्रेन परिचालन में निरंतर असुविधा हो रही है और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समयावधि का लगभग आधा समय बीत चुका है, इसके बावजूद कार्य प्रारंभ न होना प्रशासनिक उदासीनता और यात्रियों के प्रति अन्यायपूर्ण रवैया दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरगुजा संभाग मुख्यालय का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन होने के बावजूद अंबिकापुर में यात्री सुविधाओं का पर्याप्त सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया है,जबकि यहां यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रेलवे प्रबंधन द्वारा अवगत कराया गया कि अतिरिक्त प्लेटफार्म निर्माण प्रारंभ करने के लिए अंबिकापुर में स्थित गुड्स शेड के कार्य को 1 मार्च से डिनोटिफाइड कर दिया गया है,जिसके बाद यह क्षेत्र अतिरिक्त प्लेटफार्म निर्माण के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बैठक में जोनल कमेटी के सदस्य मुकेश तिवारी ने निर्धारित मापदंडों के अनुरूप समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण करने को कहा। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 6 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज तथा डिजिटल कोच डिस्प्ले प्रणाली की स्थापना हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। पिट लाइन निर्माण कार्य को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। जेडआरयूसीसी सदस्य द्वारा पिट लाइन कार्य को तेज गति से पूर्ण किए जाने की मांग पर रेलवे प्रशासन ने चालू वित्तीय वर्ष के भीतर इस कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। वहीं स्टेशन तक पश्चिम दिशा से पृथक पहुंच मार्ग की मांग पर रेलवे ने बताया कि इस संबंध में राज्य शासन के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इसकी संभाव्यता का परीक्षण कराया जाएगा। प्रस्ताव यदि तकनीकी, भूमि उपलब्धता एवं यातायात दृष्टि से व्यवहार्य पाया जाता है तो नियमानुसार इसके निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र प्रारंभ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

नई ट्रेन के संचालन का प्रस्ताव

जेडआरयूसीसी सदस्य मुकेश तिवारी ने बैठक में कहा कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अब यह आवश्यक और व्यावहारिक हो गया है कि अंबिकापुर से रायपुर के लिए एक सीधी इंटरसिटी ट्रेन प्रतिदिन प्रातः 4 बजे प्रारंभ की जाए, जो अधिकतम 11 बजे तक अपनी यात्रा पूर्ण कर यात्रियों को रायपुर पहुंचा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि इस ट्रेन की वापसी रायपुर से शाम 4 बजे हो और यह रात्रि 11 बजे तक अंबिकापुर पहुंचे। बैठक में रेलवे प्रशासन ने इस सुझाव को संज्ञान में लेने की जानकारी दी।

पार्किंग अव्यवस्था पर कार्रवाई,पार्किंग टेंडर निरस्त

रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग को लेकर हो रही असुविधाओं,मनमानी शुल्क वसूली,पिक-एंड-ड्रॉप यात्रियों से जबरन शुल्क वसूले जाने तथा पार्किंग स्थल पर सार्वजनिक रूप से शुल्क सूची प्रदर्शित न किए जाने की शिकायतों पर रेलवे प्रशासन ने जांच कराई। जांच में शिकायतें सही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। जल्द ही नई निविदा IREPS मॉड्यूल के माध्यम से आमंत्रित कर प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सूरजपुर में महाघोटाले की गूंज....7.7 एकड़ जमीन ट्रांसफर और 67.33 हेक्टेयर फर्जी रकबा का खेल

जमीन,धान और बैंकिंग का जालः शिवप्रसादनगर समिति से जुड़ा बड़ा खुलासा

- जेल में पिता,फरार बेटा...और 4728 क्विंटल धान बिक्री का रहस्य
- शिवप्रसादनगर में फर्जी पंजीयन कांडः 23 किसानों के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी?
- ठगी से जमीन तक और धान खरीदी तकः सूरजपुर में सिस्टम पर गंभीर सवाल
- 7.7 एकड़ जमीन बदली,88 हेक्टेयर पंजीयन दिखा-धान खरीदी में बड़ा खेल?
- सूरजपुर धान खरीदी घोटालाः फर्जी रकबा,बैंक ऋण और संदिग्ध रजिस्ट्री का संगम
- महाठगी का महाजालः जमीन ट्रांसफर और धान खरीदी में कथित मिलीभगत उजागर
- शिवप्रसादनगर धान खरीदी और जमीन हस्तांतरण प्रकरणः नामजद आरोपों से घिरा बहुस्तरीय मामला
- जरीफुल्ला-अशफाक उल्ला प्रकरण, 7.7 एकड़ जमीन ट्रांसफर और 23 किसानों के नाम पर फर्जी रकबा जोड़कर 4728.80 क्विंटल धान बिक्री का आरोप
- महाठगी का महाजालः फाइलें चल रही हैं या सच दब रहा है?
- जमीन गई,धान बिका,बैंक चुप...पर जांच अब तक क्यों नहीं?

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

यह कहानी केवल ठगी की नहीं है,यह कहानी उस 'सिस्टम' की है जो कागज़ पर बेहद सतर्क, नियमों में बेहद सख्त और आम आदमी के मामले में बेहद सक्रिय दिखता है–लेकिन जब मामला करोड़ों की जमीन,बैंक ऋण और धान खरीदी से जुड़ जाए,तो वही सिस्टम रहस्यमय तरीके से मौन हो जाता है,करोड़ों की ठगी के आरोपी अशफाक उल्ला,उनके पिता जरीफुल्ला,7.7 एकड़ कृषि भूमि का हस्तांतरण,तीन बैंकों का ऋण,और 23 किसानों के नाम पर 67.33 हेक्टेयर फर्जी रकबा जोड़कर 4728.80 क्विंटल धान बिक्री–इतने सारे तथ्य सामने आने के बाद भी सवाल वही है, जांच अब तक क्यों नहीं? जरीफुल्ला-अशफाक उल्ला प्रकरण और शिवप्रसादनगर धान खरीदी विवाद अब एक व्यापक जांच का विषय बन चुका है, यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो यह मामला केवल समिति स्तर की गड़बड़ी नहीं, बल्कि राजस्व, बैंकिंग और कृषि विपणन प्रणाली से जुड़े गंभीर अनियमितताओं का संकेत हो सकता है, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है–क्या प्रशासन इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएगा, या मामला दस्तावेजों तक सीमित रह जाएगा?

जमीन गायब, पर प्रशासन को खबर नहीं?

ग्राम सोनपुर,तहसील भैयाथान की 3.13 हेक्टेयर (करीब 7.7 एकड़) जमीन जरीफुल्ला के नाम से हटकर हदीस मोहम्मद, रिजवान अंसारी और साधना कुशवाहा के नाम दर्ज हो गई, समय भी कम दिलचस्प नहीं–जमानत के बाद जमीन का हस्तांतरण, आज स्थिति यह है–पिता जेल में,बेटा फरार,जमीन नए नाम पर, **सवालः** क्या यह महज संयोग है? या संपत्ति 'सुरक्षित' करने की रणनीति? अगर सब कुछ नियम अनुसार हुआ, तो प्रशासन सामने आकर स्पष्ट क्यों नहीं करता?

व्यंग्य की कड़वी सच्चाई

सूरजपुर में लगता है खेती से ज्यादा कागज उपज रहे हैं,यहां जमीन बदलती है,रकबा बढ़ता है,धान बिकता है–और सिस्टम शांत रहता है,आम आदमी की फाइल महीनों घूमती है,लेकिन करोड़ों की जमीन और हजारों क्विंटल धान के मामले में सन्नाटा,यह सन्नाटा ही सबसे बड़ा सवाल है।

पीड़ित कहां जाए?

सबसे दुःखद पहलू यह है कि जिन लोगों के पैसे ठगे गए,वे अब भी इंतजार में हैं,जमीन बिक गई,आरोपी फरार है,पिता जेल में है, धान बिक गया,पैसा किसे मिला–स्पष्ट नहीं और प्रशासन? शायद फाइल का इंतजार कर रहा है।

जांच होगी या इंतजार?

यह मामला जांच योग्य है या नहीं–यह तय करना प्रशासन का काम है,लेकिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहना कठिन है कि यह 'साधारण' प्रकरण है,जब तक जमीन की बिक्री प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती,बैंक ऋण स्थिति सार्वजनिक नहीं होती,धान खरीदी का सत्यापन नहीं होता,तब तक यह मामला महाठगी के साथ-साथ प्रशासनिक निष्क्रियता की कहानी भी बना रहेगा,और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है–क्या जांच होगी,या फाइलें ही न्याय का इंतजार करती रहेंगी?

प्रशासनिक जांच क्यों जरूरी?

यह मामला केवल ठगी का नहीं,बल्कि राजस्व विभाग,उप-पंजीयक कार्यालय,बैंकिंग प्रणाली,धान खरीदी केंद्र,सहकारी समिति सभी से जुड़ा है, इतने स्तरों पर विसंगति की आशंका हो और जांच न हो–यह सामान्य स्थिति नहीं मानी जा सकती।

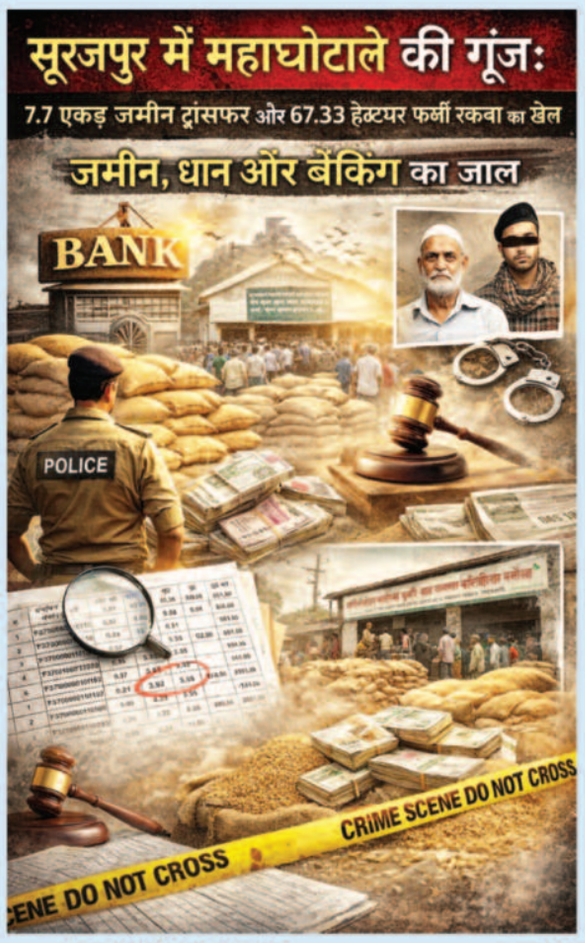

धान खरीदी का चमत्कार

अगस्त में फसल बोई गई, नवंबर में जमीन बिकी,और धान नए मालिकों के नाम पर खरीदा गया, Farmer Portal में 'हाँ (DCS द्वारा प्राप्त)' दर्ज है,205 क्विंटल धान शिवप्रसादनगर केंद्र में स्वीकृत, नियम कहता है–जिसने बोया वही बेचेगा, लेकिन यहां नियम शायद 'अपडेट' हो गया,आम किसान की फसल एक अक्षर की त्रुटि पर रिजेक्ट हो जाती है,यहां जमीन बदली, मालिक बदला,लेकिन धान खरीदी में कोई अड़चन नहीं,क्या यह दक्षता है या चयनात्मक सक्रियता?

क्या शिकायत नहीं हुई?

सूत्र बताते हैं कि शिकायतें की गईं। दस्तावेज सामने आए,तो क्याः शिकायत अधूरी थी? दस्तावेज अपूर्ण थे? या फाइल किसी अलमारी में आराम कर रही है? प्रशासन अक्सर कहता है– 'जांच जारी है।' लेकिन यहां सवाल है– क्या जांच शुरू भी हुई?

क्या यह 'जांच से परे' मामला है?

अगर सब कुछ नियम के तहत हुआ है, तो प्रशासन को डर किस बात का? जांच बैठाइए,रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए, सच्चाई सामने लाइए, लेकिन जब जांच ही नहीं होती,तो संदेह गहराता है,क्या प्रभावशाली नाम शामिल हैं? क्या दबाव है? क्या सिस्टम अपने ही सिस्टम की जांच से हिचक रहा है?

भाग 1: जरीफुल्ला-अशफाक उल्ला प्रकरण और 7.7 एकड़ जमीन का हस्तांतरण

ग्राम सोनपुर,तहसील भैयाथान,जिला सूरजपुर में दर्ज लगभग 3 .13 हेक्टेयर (करीब 7 .7 एकड़) कृषि भूमि,जो पूर्व में जरीफुल्ला (पिता – ठगी आरोपी अशफाक उल्ला) के नाम दर्ज थी,अब राजस्व रिकॉर्ड में निम्न नामों पर दर्ज बताई जा रही है: हदीस मोहम्मद,रिजवान अंसारी, साधना कुशवाहा, अशफाक उल्ला पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले दर्ज बताए गए हैं, जरीफुल्ला सह-आरोपी रहे हैं,जमानत मिलने के बाद नवंबर 2025 में पूरी जमीन का हस्तांतरण हुआ, वर्तमान में पिता जेल में, बेटा फरार बताया जा रहा है।

बैंक ऋण का मुद्दा

सूत्रों के अनुसार संबंधित भूमि पर,HDFC बैंक,जिला सहकारी केंद्रीय बैंक,छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का ऋण दर्ज था,प्रश्न यह उठता है कि यदि ऋण लंबित था तो बिना एनओसी और बंधक हटाए रजिस्ट्री किस आधार पर हुई?

शिवप्रसादनगर समिति में फर्जी पंजीयन कर धान बिक्री का आरोप

ओड़गी ब्लॉक अंतर्गत शिवप्रसादनगर समिति में वर्ष 2024-25 के दौरान 23 किसानों के नाम पर वास्तविक रकबे से अधिक भूमि जोड़कर धान विक्रय दिखाए जाने की शिकायत सामने आई है।

तालिका के अनुसार कुल स्थिति

- कुल वास्तविक रकबाः 20.94 हेक्टेयर
- दर्ज फर्जी रकबाः 67.33 हेक्टेयर
- कुल पंजीयन रकबाः 88.27 हेक्टेयर
- कुल धान बिक्रीः 4728.80 क्विंटल

आरोप है कि समिति प्रबंधक एवं धान खरीदी प्रभारी ने कथित रूप से बैंक से जुड़े व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर अतिरिक्त रकबा जोड़कर धान बिक्री दर्शाई।

नामजद किसानों के उदाहरण (तालिका अनुसार)

पंजीयन कोड	किसान का नाम	सही रकबा	दर्ज फर्जी रकबा	कुल पंजीयन	कुल धान बिक्री (क्विंटल)
TF3700080101875	दोसल मो.	0.21	2.61	2.82	145.20
TF3700080101640	कृष्णा सिंह	0.29	2.28	2.57	126.40
TF3700080101602	रामसाय	0.84	3.52	4.36	404.40
TF3700080101648	संताबाई	0.45	6.31	6.76	366.40
TF3700080101701	शिवनाथ	0.54	5.41	5.95	419.60
TF3900340101467	धनूराम	2.05	2.48	4.53	418.80
TF3728102317198	विजय कुमार	0.36	4.30	4.66	441.20

कई मामलों में सही रकबा अत्यंत कम है,जबकि पंजीयन कई गुना अधिक दर्शाया गया।

फसल बीमा और ऋण वितरण में भी आरोप

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि कथित रूप से फर्जी तरीके से निकाली गई, दो करोड़ रुपये से अधिक का पशुपालन ऋण किसानों के नाम पर वितरित किया गया,20 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाया गया है, पूर्व में थाना झिलमिली (भैयाथान) में धारा 420, 409, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज हुआ था,आरोपी को जेल भेजा गया। जमानत पाने के लिए 62,61,930 जमा किए गए।

दोनों मामलों के बीच संभावित कड़ी?

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि जमीन हस्तांतरण, बैंक ऋण, धान खरीदी में फर्जी रकबा, फसल बीमा आहरण ये सभी घटनाएं अलग-अलग नहीं बल्कि आपस में जुड़ी हो सकती हैं, यदि यह सिद्ध होता है कि फर्जी रकबा जोड़कर सरकारी राशि निकाली गई और संपत्ति हस्तांतरण संभावित कुर्की से बचने के लिए किया गया, तो मामला बहुस्तरीय आर्थिक अपराध का रूप ले सकता है।

जांच की मांग,स्थानीय नागरिकों और शिकायतकर्ताओं की मांग है कि...

- जरीफुल्ला की जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया की जांच हो।
- बैंक एनओसी की स्थिति स्पष्ट की जाए।
- 23 किसानों के रकबे का भौतिक सत्यापन हो।
- धान खरीदी केंद्र के अधिकारियों की भूमिका जांची जाए।
- आर्थिक अपराध शाखा से स्वतंत्र जांच कराई जाए।

सब जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हेतु नेशनल टीम में सूरजपुर से 2 कोच चयनित

हुगली (पश्चिम बंगाल) में 24 फरवरी से 1 मार्च तक होगा आयोजन

-संवाददाता-
सूरजपुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

46वीं सब जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 24 फरवरी से 1 मार्च तक पश्चिम बंगाल के हुगली में किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य की बालक एवं बालिका दोनों वर्गों की टीमें हिस्सा लेंगी।

इस प्रतियोगिता के लिए नेशनल टीम में सूरजपुर जिले से दो सहायक कोचों का चयन किया गया है– बालक वर्ग हेतुः रविंद्र सिंह (निवासी सूरजपुर) बालिका वर्ग हेतुः हेमंत कुमार (निवासी लटोरी, सूरजपुर) इन दोनों का चयन सूरजपुर जिले के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है, सूरजपुर से दो कोचों का नेशनल टीम में चयन यह दर्शाता है कि जिले में वॉलीबॉल खेल के प्रति निरंतर मेहनत और समर्पण रंग ला रहा है, आने वाली प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है।

जिले के लिए बड़ी उपलब्धि–सूरजपुर अमेच्योर वॉलीबॉल संघ के जिला अध्यक्ष अजय गोयल ने इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए दोनों कोचों को शुभकामनाएं दीं और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की कामना की,जिला सचिव रामशृंगार यादव ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह सूरजपुर जिले की खेल प्रतिभा और सतत प्रयासों का परिणाम है। संघ द्वारा निरंतर टीमों से संपर्क और मार्गदर्शन के कारण जिले को नई पहचान मिल रही है।

राज्य स्तर से भी बधाई...

छत्तीसगढ़ स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश गगड़ा, उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम खान एवं सचिव हेम प्रकाश नायक ने सूरजपुर अमेच्योर वॉलीबॉल एसोसिएशन को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए आभार व्यक्त किया।

स्थानीय स्तर पर उत्साह

चयन की खबर मिलते ही खेल प्रेमियों और संघ पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कोषाध्यक्ष राजनाथ गुप्ता, दिनेश साहू, संतोष सिंह, अरुण गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों एवं क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और उम्मीद जताई कि दोनों कोच राष्ट्रीय स्तर पर अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सूरजपुर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे।

खाते में ट्रांसफर कर झांसा,1 लाख की ठगी

साइबर सिंडीकेट का खुलासा,चार आरोपी गिरफ्तार,मोबाइल जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

थाना गांधीनगर क्षेत्र में साइबर ठगी के एक मामले में पुलिस ने आपराधिक सिंडीकेट का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा अपराध से संबंधित रकम अलग-अलग खातों में मंगवाकर नगद निकालने और कमीशन लेने का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार सकालो निवासी सुजीत मंडल ने 16 नवंबर 2025 को थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 1 नवंबर को उसकी दुकान 'काली माई च्वाइस सेंटर' पर बरवल चम्पारण (बिहार) निवासी अनीश गिरी नामक युवक आया। उसने स्वयं को सब्जी विक्रेता बताया और खाता सही से संचालित नहीं होने की बात कहकर एक लाख रुपये प्रार्थी के खाते में ट्रांसफर करवा दिए। इसके बाद प्रार्थी ने उक्त राशि

नगद युवक को दे दी। बाद में जानकारी मिली कि ट्रांसफर की गई रकम अपराध से संबंधित थी। इसके चलते प्रार्थी का बैंक खाता ब्लॉक हो गया और उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। मामले में अपराध क्रमांक 649/25 धारा 318(4) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।

सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्य से खुलासा : विवेचना के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी सद्दाम अंसारी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने साथी अनीस गिरी और अन्य के साथ मिलकर अपराध की रकम विभिन्न खातों में मंगवाकर सीडीएम मशीन से ट्रांसफर और निकासी करता था। इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता था। मामले में धारा 61(2) और 317(4) बीएनएस जोड़ी गई। सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आगे की कार्रवाई में अनीस गिरी और वर्षा सिंह पोर्ते को भी गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।

फर्जी नाम से आया था मुख्य आरोपी : दुकान पर स्वयं को अनीश गिरी बताने वाले व्यक्ति की तलाश में पुलिस ने अनूप कुमार चौबे (30), निवासी केतात रेहला जिला पलामू (झारखंड),हाल मुकाम बौरीपारा केनाबांध अंबिकापुर को पकड़ा। पूछताछ में उसने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल जब्त किया गया है।

स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम : श्याम बिहारी जायसवाल

जिला अस्पतालों और मातृ

शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान,बजट में जिला स्तर की स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं

» 220 बिस्तर जिला चिकित्सालय अंबिकापुर का भवन निर्माण

» 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय धमतरी का निर्माण

» 200 बिस्तर मातृ-शिशु अस्पताल (कालीबाड़ी, रायपुर) की स्थापना

» 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिए सेटअप इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय स्तर पर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी और बड़े शहरों पर दबाव कम होगा।

अस्पताल,मेडिकल कॉलेज और कैशलैस इलाज : बजट में स्वास्थ्य को प्राथमिकता...

स्वास्थ्य अधोसंरचना को नई रफ्तार : जिला अस्पतालों से लेकर कैंसर इंस्टीट्यूट तक घोषणा

स्वस्थ छत्तीसगढ़ का संकल्प : बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे बड़ी सौगात...

कैशलैस सुविधा और 25 नए डायलिसिस केंद्र: स्वास्थ्य बजट में ऐतिहासिक निर्णय...

-रवि सिंह-

एमसीबी,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के संकल्प बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को व्यापक और ऐतिहासिक प्राथमिकता दी गई है, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बजट को प्रदेश की 3 करोड़ जनता के बेहतर स्वास्थ्य,सामाजिक सुरक्षा और समग्र विकास के लिए समर्पित बताया है, उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा... छत्तीसगढ़ सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने का व्यापक संकल्प लिया गया है,राज्य में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं,मेडिकल शिक्षा और उन्नत उपचार व्यवस्था के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं,जो प्रदेश को स्वस्थ और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं।

चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा,प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कई नए संस्थानों की घोषणा की गई है...

» दुर्ग, कोंडागांव, जशपुर और रायपुर में जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र

» दंतेवाड़ा,मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज

» कांकेर,कोरबा,मनेन्द्रगढ़,सरिया और महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज

» राजनांदगांव में फिजियोथेरेपी कॉलेज

» रायपुर में उन्नत कार्डियक इंस्टिट्यूट

» बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट

» रायपुर में राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज इन संस्थानों से प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा में स्थानीय अवसर मिलेंगे और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी।

कैंसर उपचार को मजबूती

बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान के लिए सेटअप प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर रोगियों को प्रदेश के भीतर ही उन्नत उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। इससे बाहर रेफर होने की आवश्यकता कम होगी और मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा।

नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत

प्रदेश के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दंतेवाड़ा,मनेन्द्रगढ़,कबीरधाम,जांजगीर-चांपा,जशपुर में नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन की व्यवस्था की गई है,इसके साथ ही कांकेर,कोरबा,मनेन्द्रगढ़ और महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए जाएंगे, जिससे प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी।

एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट को उन्नयन

रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (मेकाहारा) में उपकरण, बिस्तरों और AI आधारित उपचार सुविधाओं के उन्नयन के लिए 10 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे हृदय रोगियों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित उपचार मिल सकेगा।

मेडिकल विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल निर्माण

मेडिकल शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,रायपुर,शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय,रायपुर में छात्र-छात्राओं एवं इंटर्न्स के लिए हॉस्टल निर्माण हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे चिकित्सा विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी।

स्वस्थ और विकसित छत्तीसगढ़ की ओर

सुदृढ़ स्वास्थ्य अधोसंरचना,आधुनिक तकनीक और बेहतर उपचार सुविधाओं के साथ राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र विकास की प्राथमिकता में है,यह बजट प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों को बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बड़ा बजटीय प्रावधान

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बजट में जनस्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं: 1,500 करोड़ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, 2,000 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,25 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण,इन प्रावधानों से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होगा।

गुणवत्ता जांच और पारदर्शिता

खाद्य पदार्थों और दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंटिग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है,इससे जांच क्षमता और पारदर्शिता दोनों मजबूत होंगी, साथ ही, सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में अधोसंरचना विस्तार हेतु भी 25 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

डायलिसिस और जन औषधि केंद्रों का विस्तार

प्रदेश में 25 नए डायलिसिस केंद्र और 50 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को सस्ती और सुलभ उपचार सुविधा मिल सकेगी।

शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा

स्वास्थ्य मंत्री ने इसे बजट की ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय बड़ी राहत देगा। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी।

स्वस्थ छत्तीसगढ़ की ओर

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का संकल्प है, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए ये प्रावधान प्रदेश को चिकित्सा सुविधाओं, अधोसंरचना और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, लक्ष्य स्पष्ट है – उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं, बिना वित्तीय बोझ के हर नागरिक तक पहुंचाना।

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक/973/स्टोर/2026 अम्बिकापुर,दिनांकः 21/02/26

ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम निविदा आमंत्रण सूचना

राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) की ओर से वाहन स्टैण्ड संचालन के निविदा हेतु फर्मों / अभिकरणों से राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) में वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु ऑनलाईन निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में देखा जा सकता है।

क्र.	निविदा का नाम	सी.जी.ई. प्रोक्यो. निविदा क्रमांक	ऑनलाईन जमा करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	ऑनलाईन से जमा जमा करने की अंतिम तिथि समय	भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
1	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर में वाहन स्टैण्ड का संचालन	186085	26.2.26, 10:00 AM	2.03.2026 02:00 PM	2.03.2026 03:00 PM	2.03.2026 04:00 PM

स्थान - कार्यालय,संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय,अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा (छ.ग.)

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय,अम्बिकापुर सरगुजा (छ0ग0)

जी नंबर-252606684/3

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0/...../अ-20 (1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मलय भट्टाचार्य आ0 शिशुरंजन भट्टाचार्य, निवासी वार्ड क्रमांक 15 देवीगंज वार्ड, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि मोहल्ला खुटेनपारा, नगर अम्बिकापुर, शीट नंबर- 02 स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 388/1, 389/1 रकबा 0.03, 0.03 एकड़ भूमि की लीज समाप्ति तिथि 31.03.2026 है। जिसके नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मय मेंटनेश खसरा की प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 09/03/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक- 19/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0/...../अ-20 (3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कैलाश कुमार बुधिया आ0 स्व0 रामेश्वर प्रसाद बुधिया, निवासी सदर रोड़ अम्बिकापुर, वर्तमान निवासी- शंकरनगर, रायपुर की ओर से आम मुख्तार - आदित्य बुधिया पिता कैलाश कुमार बुधिया निवासी सदर रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने मोहल्ला-सदर रोड़, नगर अम्बिकापुर स्थित स्वामित्व एवं आधिपत्य की शीट नम्बर - 08 मोहल्ला सदर रोड,नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 2573/4 रकबा 0.06 3/4 एकड़ भूमि में से 1129 वर्गफीट भूमि को अनावेदक/ केता मिलिन्द अग्रवाल आ0 महेश कुमार केडिया, निवासी- मनेन्द्रगढ़ रोड़ पटपरिया, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ0ग0 के पास बिक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 09/03/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 18.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0/...../अ-6 /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सूर्य बलि सिंह चंदेल आ.स्व. बंकराज सिंह चंदेल, उम्र 68 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 6 फोरेस्ट कॉलोनी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पिता बंकराज सिंह चंदेल के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, शीट में 3 मोहल्ला सत्तीपारा स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 832/4 रकबा 0.15 3/4 एकड़ भूमि है। आवेदक के पिता बंकराज सिंह चंदेल की मृत्यु दिनांक 28.12.2025 को हो गई है जिस कारण उक्त भूखण्ड से उनका नाम विलोपित कर फौति नामांतरण के आधार पर स्वयं के नाम से उक्त भूखण्ड का रिकार्ड दुरुस्त किये जाने हेतु आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109 110 भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा सा तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनाक 09/03/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दादा पा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18/02/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी बरियों जिला-बलरामपुर,रा.गं.छ.ग.

रा0प्र0क्र0-/ब-121 /2024-25
ग्राम-सिधमा प0ह0नं0-उप तह0बरियों

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम सिधमा प0ह0नं0- उप तहसील बरियों जिला बलरामपुर रा0गंज को सूचित किया जाता है कि आवेदक मालिकसाय ..आ0 / पति.. स्व0 जयश्री जाति कंवर निवासी ग्राम सिंधमा तहसील- राजपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा स्वंय के बाबा राजनाथ आ0 मोती का मृत्यु दिनांक 10.08.2001 को ग्राम सिधमा घर में हुई है। किन्तु जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यालय में नियत समय में अज्ञानता वश कार्य व्यस्तता के कारण पंजीयन नहीं करा पाने के कारण पंजीयन हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र पेश ।

उपरोक्त जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में उज्जर आपत्ति या दावा हो या हितबद्ध पक्षकार हो तो वह स्वंय, अथवा वैध अभिकर्ता अथवा अभिभाषक के दिनांक- 11/03/2026 को न्यायालयीन समय में दावा या आपत्ति हो तो पेश कर सकता है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।

अतः आज दिनांक- 25/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर से जारी किया गया।

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी बरियों जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

न्यायालय तहसीलदार लटोरी जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क्र0- ब-121 वर्ष
ग्राम- लटोरी प0ह0न0.....

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शेषन केवट आ0 मोहन राम केवट जाति केवट निवासी ग्राम लटोरी प0ह0नं0 .... रा0नि0म0 लटोरी तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के माता स्व. जयमोती का मृत्यु दिनांक 10/12/2014 को ग्राम, तटोरी में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 06-3-26 तक अपना आपत्ति इस न्यायायल में पेश कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16-2-26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।
पेशी दिनांक - 06-3-26
जारी दिनांक - 16-2-20

सील — कार्यपालिक दण्डाधिकारी लटोरी जिला सूरजपुर छ0ग0

सतपुरिया वनक्षेत्र में 73 हाथियों का दल सुरक्षित रूप से कर रही विचरणरत

-संवाददाता-

जशपुरनगर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तपकरा परिक्षेत्र अंतर्गत सतपुरिया जंगल में 14 दिसम्बर 2025 से 37 हाथियों का एक दल तथा 25 फरवरी 2026 से 36 हाथियों का अन्य दल कुल 73 हाथियों का समूह विचरणरत है। वर्तमान में उक्त सभी हाथी सतपुरिया वनक्षेत्र के भीतर ही सुरक्षित रूप से विचरण कर रहे हैं। अब तक हाथियों का दल वन क्षेत्र से बाहर नहीं आया है तथा किसी प्रकार की जनहानि, जन घायल अथवा मकान क्षति की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। वन क्षेत्र से बहार निकलकर फसल क्षति की घटना की जाती है। परन्तु स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में एवं सामान्य है। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में निरंतर सतर्कता बरती जा रही है। आर.आर.टी. के साथ नियमित गश्ती की जा रही है तथा हाथियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त सतपुरिया जंगल से लगे आस-पास के ग्रामों में मुनादी, सूचना प्रसारण एवं व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से ग्रामीणों को निरंतर सतर्क किया जा रहा है।

CMYK

» झुमका तक सिमटा विकास? कोरिया की बड़ी उम्मीदें अधूरी...

» घोषणाओं से हकीकत तक: कोरिया को कब मिलेगा मजबूत नेतृत्व?

» विकास पुरुष की तलाश में कोरिया– इतिहास दोहराएगा या बदलेगा?

» विभाजन के बाद विकास का विभाजन? कोरिया की राजनीति पर बड़ा प्रश्न

» बजट में सूखा,उम्मीदों में दरार–कोरिया का अगला चेहरा कौन?

» विकास नहीं तो झुनझुना सही! बजट पर कोरिया का अनोखा विरोध

» कोरिया के हिस्से आया 'खाली पन्ना' बजट! बजट 2026: सौगातों की सूची में कोरिया गायब?

» जनता पूछे सवाल – क्या कोरिया की आवाज कमजोर पड़ गई?

» झुनझुने से गूंजा कोरिया,बजट पर उठी नाराज़गी की झंकार, विकास की जगह प्रतीकात्मक सौगात?

क्या कोरिया झुमका तक सिमट गया?

स्थानीय चर्चाओं में एक वाक्य बार-बार सुनाई देता है–क्या कोरिया अब सिर्फ झुमका तक रह गया है? झुमका डैम और उसके आसपास के विकास कार्यों की चर्चा जरूर होती है, लेकिन जिला मुख्यालय और अन्य क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं की कमी महसूस की जा रही है। क्या विकास का दायरा सीमित हो गया है? क्या बाकी क्षेत्र प्रतीक्षा में हैं?

बड़ा सवाल: अब कौन बनेगा विकास पुरुष?स्थिति का सार यही है

कोरिया की जनता नेतृत्व से प्रतीकात्मक नहीं,ठोस परिणाम चाहती है,जनता पूछ रही है कौन ऐसा होगा जो जिले के लिए दीर्घकालिक योजनाएं लाए? कौन बजट में कोरिया की मजबूत पैरवी कर पाएगा? किस पर भरोसा किया जाए कि जिला फिर से बड़े विकास मानचित्र पर लौटे? विकास पुरुष का तमगा सिर्फ भाषणों से नहीं मिलता–उसके लिए योजनाओं की स्वीकृति,समयबद्ध क्रियान्वयन और राजनीतिक प्रभाव जरूरी होता है,कोरिया की जनता अब घोष णाओं से आगे बढ़कर परिणाम चाहती है, आने वाले समय में यही तय करेगा कि जिले की राजनीति में अगला विकास पुरुष कौन कहलाएगा–या फिर यह उपाधि इतिहास की किताबों तक सिमट जाएगी।

विभाजन के बाद से जारी है 'संकुचन'

कोरिया जिले का विभाजन जब हुआ था,तब इसे प्रशासनिक सुविधा बताया गया,लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर स्वीकार किया, पर अब स्थिति यह है कि– मेडिकल कॉलेज अलग जिले को,नई परियोजनाएं अलग जिले को,बजट की प्राथमिकताएं अलग जिले को और कोरिया के हिस्से रह गई सिर्फ यादें और उम्मीदें।

संकल्प बजट में कोरिया को मिला झुनझुना

जनता ने बजाकर जताया रोष!

★ संकल्प बजट में कोरिया के हिस्से आया संकल्प... विकास का नहीं, धैर्य का!

★ एमसीबी पर मेहरबानी, कोरिया पर खामोशी-नेता प्रयासहीन या सरकार उदासीन

★ कोरिया का विकास ठहरा क्यों अब कौन बनेगा जिले का नया विकास पुरुष

★ विरासत से विराम तक: कोरिया में विकास की रफ्तार पर सवाल

★ कभी सौगातों की धरती, आज बजट से मायूस–कोरिया किसके भरोसे?

-रवि सिंह-

कोरिया/एमसीबी,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े उत्साह के साथ वर्ष 2026-27 का संकल्प बजट पेश किया, संकल्पों की फेहरिस्त लंबी रही,घोषणाओं की चमक दमक भी कम नहीं थी,लेकिन जब कोरिया जिले के लोग अपने हिस्से का पन्ना पलटने लगे तो उन्हें बजट में सिर्फ शब्द मिले– सौगात नहीं, कहने को बजट प्रदेश के संतुलित विकास का दस्तावेज है,लेकिन कोरिया जिले के लिए यह सूखा अध्याय साबित हुआ,वहीं नवगठित एमसीबी जिला जैसे किसी विशेष कृपा सूची में शामिल दिखाई दिया।

बता दे की छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का दूसरी पारी का बजट सदन में पेश हो चुका है, बजट को संकल्प बजट नाम दिया गया है और प्रदेश के लिए कई घोषणाएं वित्तीय प्रबंधन के साथ किए जाने की बात बजट में शामिल है,बजट में कई जिलों को भी प्रदेश के बहुत कुछ मिला है लेकिन कांग्रेस शासनकाल में विभाजित कोरिया जिले को बजट से कोई बड़ी सौगात मिलने की कोई सूचना सामने नहीं आई,जिले के भाजपा नेताओं ने बजट की खूबियों का तो बखान किया लेकिन जब जिले को मिली उपलब्धियों की समीक्षा बजट से की गई कोई ठोस कारण बखान का समझ में नहीं आया,कोरिया जिला विभाजन पश्चात उपेक्षित जिला बनकर रह गया यह इस बजट से साबित हुआ और जिले से अलग जाकर गठित नए जिले को मिली बजट सौगातें भी साबित करती हैं कि नव गठित जिले एमसीबी को बहुत कुछ मिल गया है इस बजट से, वैसे बजट से उपेक्षित रहे कोरिया जिले की ऐसी स्थिति क्यों बनी बजट से कुछ क्यों नहीं मिला इसका कारण समझ से परे है, क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिले के विधायक, नेताओं ने प्रयास नहीं किया कि कुछ जिले को मिल सके या नेताओं,विधायकों के मांगों की अनदेखी की गई बजट में? ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि कोरिया जिले को कई उम्मीदें थीं बजट से जो पूरी नहीं हुई,बजट 2026 कोरिया जिले के लिए सूखा बजट रहा।

विकास अब सिर्फ झुमका तक?

जिले में चर्चा है कि विकास की पूरी कहानी अब झुमका तक सीमित है,झुमका में योजनाएं, झुमका में घोषणाएं,झुमका में तस्वीरें...तो क्या बाकी कोरिया अब सिर्फ नक्शे में बचा है? जनता पूछ रही है क्या जिला मुख्यालय का विकास सिर्फ फाइलों में रहेगा? क्या बाकी ब्लॉक अगली सूची का इंतजार करते रहेंगे?

नेताओं के प्रयास में कमी या अनदेखी?

यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या कोरिया के जनप्रतिनिधियों ने ठोस पैरवी नहीं की? या फिर उनकी मांगों को प्राथमिकता सूची में नीचे रख दिया गया? सत्ता के गलियारों में आवाज वही सुनी जाती है जो लगातार गूंजे,अगर आवाज धीमी हो जाए,तो बजट के पन्ने भी चुप रह जाते हैं।

बजट का आईना और कोरिया की परछाई

बजट सरकार की प्राथमिकताओं का आईना होता है, इस आईने में इस बार कोरिया की परछाई धुंधली दिखी, एमसीबी की तस्वीर चमकदार है, कोरिया की फीकी,अब यह समय है आत्ममंथन का–नेताओं के लिए भी और जनता के लिए भी,क्योंकि अगर जिला अपनी आवाज मजबूत नहीं करेगा,तो संकल्प बजट हर साल संकल्प ही देता रहेगा– सौगात नहीं।

कोरिया के विकास पुरुष का खाली होता स्थान: अब किस पर टिकेगी उम्मीद?

कोरिया जिले की राजनीति और विकास यात्रा में कभी विकास पुरुष की पहचान एक मजबूत प्रतीक हुआ करती थी,लंबे समय तक बैकुंठपुर से विधायक रहे और पूर्व मंत्री रामचंद्र सिंहदेव का कार्यकाल सिंचाई परियोजनाओं, जलाशयों, बांधों और संरचनात्मक विकास के लिए याद किया जाता है,उस दौर में जिला बजट से निराश नहीं होता था–लघु और दीर्घ सिंचाई योजनाएं आज भी उनकी विरासत मानी जाती हैं,इसी क्रम में भईयालाल राजवाड़े के पूर्व के दो कार्यकाल भी उपलब्धियों वाले माने गए,संसदीय सचिव और मंत्री रहते हुए जिले को कई सौगातें मिलीं। उस समय यह धारणा बनी कि कोरिया की आवाज सत्ता के गलियारों तक प्रभावी ढंग से पहुंचती है।

बजट आया...सौगात नहीं,इसलिए कोरिया ने बजाया झुनझुना!

कोरिया शहर में बजट में जिले को कोई बड़ी घोषणा न मिलने से नाराज़ एक युवक ने सड़क पर खड़े होकर हाथों में झुनझुना लेकर विरोध का अनोखा तरीका अपनाया।

दोनों हाथों में रंगीन झुनझुना लिए युवक का संदेश साफ है

जब विकास नहीं मिला,तो कम से कम आवाज तो हो! तस्वीर में युवक बाजार क्षेत्र में खड़ा दिखाई दे रहा है, मानो यह प्रतीक हो कि आम नागरिक अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बजट पर प्रतिक्रिया देने वाला बन चुका है।

कोरिया बनाम एमसीबी: उपलब्धियों की विरासत, बजट की उम्मीदें और नेतृत्व पर उठते सवाल

कोरिया जिले के इतिहास पर नजर डालें तो यह जिला लंबे समय तक अपनी हरियाली,सिंचाई परियोजनाओं और योजनाबद्ध विकास के लिए जाना जाता रहा है, पूर्व मंत्री एवं बैकुंठपुर विधानसभा से कई बार विधायक रहे रामचन्द्र सिंहदेव के कार्यकाल को जिले की विकास यात्रा का स्वर्णिम दौर माना जाता है।

स्वर्णिम दौर: सिंचाई और संरचनात्मक विकास

रामचन्द्र सिंहदेव के कार्यकाल में लघु एवं दीर्घ सिंचाई योजनाओं,जलाशयों और बांधों का निर्माण हुआ, जिसने जिले की कृषि व्यवस्था को नई दिशा दी। हसदेव अंचल की सिंचाई परियोजनाएं आज भी जिले की हरियाली और कृषि उत्पादन का आधार मानी जाती हैं. उस दौर में जिला बजट से कभी निराश नहीं हुआ–विकास योजनाएं निरंतर मिलती रहीं और कोरिया की पहचान मजबूत होती गई।

भईयालाल राजवाड़े का कार्यकाल: निरंतरता और सौगातें

इसी क्रम में वर्तमान दौर से पहले के कार्यकालों में भईयालाल राजवाड़े का नाम भी उपलब्धियों के साथ जुड़ा रहा,संसदीय सचिव और मंत्री रहते हुए उन्होंने जिले के लिए कई विकास कार्य स्वीकृत कराए,उनके पूर्व के कार्यकाल में कोरिया को बजट से अपेक्षा से बेहतर प्रावधान मिलते रहे–यह धारणा आज भी जनमानस में मौजूद है।

इस पारी में क्यों अछूता रह गया कोरिया?

वर्तमान बजट में कोरिया जिला, खासकर जिला मुख्यालय,अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया। शहर की सड़कों के चौड़ीकरण जैसी बहुप्रतीक्षित मांग भी बजट में शामिल नहीं हुई। यह वह एक बड़ी अपेक्षा थी जिस पर शहरवासियों की निगाहें टिकी थीं, बजट शब्द भले ही आम जनता के लिए एक औपचारिक सरकारी दस्तावेज हो–वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, प्रावधान और समीक्षाएं आमजन कम ही समझते हैं–लेकिन अपने क्षेत्र के हिस्से पर सबकी नजर रहती है। जब पड़ोसी जिले को अधिक मिलता दिखाई देता है,तो तुलना स्वाभाविक है।

एमसीबी को मिली सौगातें,तुलना ने बढ़ाया सवाल

कोरिया के विभाजन के बाद बने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला (एमसीबी) को इस बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान मिले हैं,मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के लिए बजट में प्रावधान और नगरीय निकायों में व्यापक वित्तीय आवंटन ने एमसीबी को विकास की नई गति दी है,यही तुलना अब कोरिया में चर्चा का विषय है–क्या मंत्रित्व कार्यकाल का प्रभाव बजट आवंटन में परिलक्षित हो रहा है? क्या नेतृत्व की सक्रियता से क्षेत्रीय लाभ तय हो रहे हैं? यह प्रश्न सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुका है।

विभाजन की स्मृतियां और वर्तमान मायूसी

कोरिया जिले का विभाजन एक भावनात्मक विषय रहा, लोगों ने अनिच्छा के बावजूद नए जिले का स्वागत किया,लेकिन आज जब नया जिला तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है और पुराना जिला अपेक्षाकृत ठहरा हुआ प्रतीत होता है, तो विभाजन का दौर फिर चर्चा में आ जाता है,तब नेतृत्व ने विभाजन पर मौन साधा था–ऐसी धारणा जनता के एक वर्ग में रही। आज वही नेतृत्व यदि बजट और विकास योजनाओं के मामले में प्रभावी नहीं दिखता,तो सवाल उठना स्वाभाविक है।

नेतृत्व के लिए आत्ममंथन का समय?

कोरिया की जनता निराशा से अधिक स्पष्टता चाहती है– क्या योजनाएं प्रस्तावित नहीं हुईं? क्या प्रशासनिक स्तर पर कमी रही? या राजनीतिक प्रभाव घटा? इतिहास बताता है कि जब नेतृत्व सक्रिय और प्रभावी होता है तो जिला बजट से निराश नहीं होता, आज आवश्यकता है रणनीतिक प्रयासों, ठोस प्रस्तावों और समन्वित पैरवी की–ताकि कोरिया फिर से अपनी विकास यात्रा को उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा सके, जैसा उसने पहले देखा था।

अब क्यों सुनाई दे रहा है सूखा शब्द?

वर्तमान परिदृश्य इसके उलट नजर आता है, पूर्व विधायक का कार्यकाल घोषणाओं और अधूरे निर्माण कार्यों के लिए चर्चित रहा, साथ ही जिला विभाजन का निर्णय भी उसी दौर में तय हुआ, विभाजन को लेकर जनभावनाएं आज भी मिश्रित हैं–कई लोग इसे जिले की पहचान कमजोर होने के रूप में देखते हैं, 2023 के बाद शुरू हुए वर्तमान कार्यकाल में भी अपेक्षित बड़ी उपलब्धियां सामने नहीं आईं। विकास की जगह मरम्मत और छोटे कार्य अधिक दिखाई दे रहे हैं–यह धारणा जनमानस में बन रही है, घोषणाओं और क्रियान्वयन के बीच की दूरी सवाल खड़े कर रही है।

2018 के बाद से बजट में उपेक्षा?

2018 के चुनाव के बाद से कोरिया की बजटीय हिस्सेदारी को लेकर असंतोष की चर्चा लगातार रही है। मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी परियोजनाएं विभाजन के बाद अलग हुए मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला (एमसीबी) के हिस्से में चली गईं, अब तुलना स्वाभाविक है–एमसीबी को नई सौगातें मिलती दिख रही हैं, जबकि कोरिया में अपेक्षाएं अधूरी रह जा रही हैं, सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राजनीतिक प्रभाव और सत्ता में भागीदारी का सीधा असर बजट आवंटन पर पड़ रहा है?

ममता कुलकर्णी ने दिखाई दिव्या भारती की अनसीन झलक

बर्थ एनिवर्सरी पर सहेली को किया याद

मशहूर अदाकारा दिव्या भारती की आज 52वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इस मौके पर उनकी सहेली और एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने अनसीन फोटो को शेयर किया है।

90 की दशक की लोकप्रिय अदाकारा दिव्या भारती को भला कौन भूल सकता है। चंद सालों में हिंदी सिनेमा की लेडी सुपरस्टार बनने वालीं दिव्या अपने दौर की सबसे ब्यूटीफुल और टैलेंटेड अभिनेत्री में शुमार थीं। महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वालीं दिव्या भारती की आज 52 वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है।

इस मौके पर दिव्या की सहेली और मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने उनकी अनसीन फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और बर्थडे विश करते हुए उन्हें याद किया है।

ममता कुलकर्णी ने शेयर की दिव्या भारती की फोटो

बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही दौर की दो बड़ी अभिनेत्रियां आपस में अच्छी दोस्त हों। ममता कुलकर्णी और दिव्या भारती अपने समय की टॉप एक्ट्रेसेज में शुमार रहीं। आज दिव्या की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर ममता द्वारा उनकी अनसनी फोटो शेयर किए जाने से ये साफ होता है कि इनकी दोस्ती काफी गहरी थी। ममता कुलकर्णी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर दिव्या भारती संग अनदेखी तस्वीर को शेयर किया है। इस फोटो में ये दोनों अभिनेत्रियां एक संग नजर आ रही हैं।

पोस्ट में कैप्शन में ममता कुलकर्णी ने लिखा है- अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या भारती को जन्मदिन की बधाई। दिव्या आपको बर्थडे मुबारक हो।

इस तरह से ममता कुलकर्णी ने सहेली दिव्या भारती को याद किया है। आलम ये है कि सोशल मीडिया पर दिव्या और ममता की ये अनसीन फोटो तेजी से वायरल हो रही है और फैंस इस पर जमकर लाइक कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- क्या बेहतरीन फोटो है, हमने पहले नहीं देखा इसे। एक अन्य यूजर का मानना- वाकई अपने जमाने में दिव्या भारती से ज्यादा कोई और खूबसूरत नहीं था।

दिव्या भारती का रिकॉर्ड

बतौर एक्ट्रेस दिव्या भारती का करियर महज तीन तक चला। लेकिन इस दौरान उन्होंने 20 से ज्यादा मूवीज में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा। साल 1992 में दिव्या की 12 फिल्में रिलीज हुई थीं, जोकि अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं वह अपने दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी हुआ करती थीं।

मौत से 24 घंटे पहले किशोर कुमार ने रिकॉर्ड किया था आखिरी गाना

यूट्यूब पर हिट है 39 साल पुराना सॉन्ग

सुरों के सरताज किशोर कुमार ने अपने करियर में कई यादगार गीत गाए। आज हम आपको किशोर दा के आखिरी गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने मौत से ठीक 24 घंटे पहले की थी। किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के सबसे उम्दा गायकों में से एक थे। अपने सिंगिंग करियर के दौरान एक से बढ़कर एक गीत के जरिए श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचाने वाले किशोर दा का निधन 39 साल पहले हुआ था।

आज हम आपको किशोर कुमार के उस आखिरी गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने मौत से 24 घंटे पहले की थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां किशोर कुमार के कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

किशोर कुमार का आखिरी गाना

13 अक्टूबर 1987 में किशोर कुमार का निधन हृदय गति रुकने की वजह से हुआ था। उस दिन सिनेमा जगत ने सुरों के सरताज को हमेशा-हमेशा के लिए खो दिया था। इससे पहले किशोर दा ने अपनी जिंदगी के आखिरी गीत को रिकॉर्ड किया था, जो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और अभिनेत्री श्रीदेवी की फिल्म वक्त की आवाज के लिए था।

सुरों की कोकिला आशा भोसले संग मिलकर किशोर कुमार ने इस मूवी के गाने गुरु गुरु आ जाओ... के लिए सुर से सुर मिलाए थे। जी हां इसी गाने की रिकॉर्डिंग किशोर कुमार ने मौत से 24 घंटे पहले की थी। आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार इसका जिक्र मिलता है। संगीतकार बप्पी लहरी के इस गीत की रिकॉर्ड 12 अक्टूबर 1987 को हुई थी और उसके अगले दिन किशोर कुमार ने इस दुनिया के अलविदा कह दिया था। इस तरह से गुरु आ जाओ किशोर के सिंगिंग करियर का लास्ट बनकर रह गया।

यूट्यूब पर है हिट

किशोर कुमार का आखिरी गाना यूट्यूब पर काफी हिट है। 38 साल पुराना ये गीत शेमरू यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसे 25 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती का ये सॉन्ग रोमांटिक ट्रैक के तौर पर जाना जाता है। बता दें कि किशोर दा ने अपने सुनहरे गायिकी के करियर में हिंदी सहित कई भाषाओं को मिलाकर अनुमानित 16 हजार से ज्यादा गीतो को अपनी मधुर आवाज दी थी।

वाईआरएफ ने ठुकराई नेटफ्लिक्स की 215 करोड़ की डील,आलिया भट्ट की अल्फा को लेकर दिया था ऑफर

यश राज फिल्म्स ने आलिया भट्ट,शरवरी और बॉबी देओल अभिनीत अपनी स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा को सीधे ओटीटी पर रिलीज करने के नेटफ्लिक्स इंडिया के 215 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। कंपनी ने सिनेमाई अनुभव को प्राथमिकता देते हुए फिल्म को सिनेमाघरों में ही रिलीज करने की पुष्टि की है। बीते दिनों ऐसी खबर आई थी कि यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा को ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। शिव रवैल इसके निर्देशक हैं। कहा जा रहा था कि वॉर 2 को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिलने के बाद ऐसा निर्णय लिया गया। यहां तक कहा जा रहा था कि वाईआरएफ ने इसके लिए एक बड़ा ओटीटी सौदा किया है। हालांकि, वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह बड़ा ऑफर सच होने के बावजूद, वाईआरएफ ने इसे ठुकरा दिया है। इस फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी और बॉबी देओल लीड रोल में नजर आएंगे और इसे सिनेमाघरों में ही रिलीज किया जाएगा।

डायरेक्टर ने ऑफर की गार्ड की नौकरी,23 साल तक सलमान खान से रही अनबन...

सिक्किम में जन्मे डैनी डेंजोंग्पा भारतीय सिनेमा के एक सम्मानित अभिनेता हैं, जो अपनी दमदार आवाज और खलनायक भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें 2003 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। करियर की शुरुआत में उन्हें गार्ड की नौकरी का ऑफर मिला था। सलमान खान के साथ अनप्रोफेशनल व्यवहार के कारण उन्होंने 23 साल तक उनके साथ काम नहीं किया। शेरिंग फिंटसो डेंजोंग्पा भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं। वे अपनी दमदार आवाज, शानदार शैली और प्रभावशाली खलनायक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। डैनी ने हिंदी,तमिल,नेपाली और बंगाली भाषाओं में 190 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। कालीचरण,द बर्निंग ट्रेन,अग्निपथ और खुदा गवाह उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में हैं। उन्हें फिल्म जगत में अपने बेहतरीन काम के लिए 2003 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डैनी को उनके अनुशासन, समय की पाबंदी और प्रोफेशनलिज्म के लिए हमेशा सराहा जाता है।

बचपन में संगीत में थी रुचि

डैनी का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के गंगटोक शहर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत और कला में बेहद रुचि थी। पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद एक्टिंग सीखने के लिए वो एफटीआईआई आ गए। यहां से कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई में जब डैनी ने अपने करियर की शुरुआत की तो उनके पास मात्र 1500 रुपये थे। आज एक्टर के

78वें जन्मदिन के मौके पर बात करेंगे उनके जीवन से जुड़े ऐसे ही किस्सों के बारे में।

बेहद बुरी लगी थी डायरेक्टर की बात

डैनी इंडस्ट्री में गजल सिंगर के तौर पर लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआती दिनों में उन्हें रोल के लिए स्टूडियो और डायरेक्टर के घरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन कहीं भी सफलता हासिल नहीं हो रही थी। एक बार जब वे डायरेक्टर मोहन कुमार के बंगले पहुंचे, तो उन्हें गार्ड की नौकरी ऑफर की गई। यह बात उन्हें बेहद बुरी लगी। उन्होंने ठान लिया कि एक दिन वे इतने बड़े स्टार बनेंगे कि उस डायरेक्टर के बंगले के पास उनका भी बंगला होगा, और सचमुच ऐसा हुआ भी।इसके अलावा एक किस्सा ये भी है कि डेनी का बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ बड़ा विवाद था। इस वजह से डेनी 23 साल तक सलमान के साथ फिल्म करने के लिए मना करते रहे।

सलमान को सुनाई थी खरी-खोटी

दरअसल 1991 में, डैनी और सलमान ने रोमांटिक फिल्म सनम बेवफा में साथ काम किया। डैनी हमेशा की तरह समय पर सेट पर पहुंचे। लेकिन सलमान,जो उस समय इंडस्ट्री में नए थे,कई घंटे देर से आए। इससे डैनी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने फिल्म रूप के सामने सलमान को उनके अनप्रोफेशनल व्यवहार के लिए खूब खरी-खोटी सुनाई। डैनी को लगा कि देर से आना दूसरों के समय का अनादर है। उस दिन के बाद, डैनी ने फैसला कर लिया कि वह फिर कभी सलमान खान के साथ काम नहीं करेंगे। ये सिलसिला 23 सालों तक चला।हालांकि इसके बाद 2014 में, सलमान के भाई सोहेल खान द्वारा निर्देशित फिल्म जय हो में दोनों अभिनेता एक बार फिर साथ आए। डैनी ने फिल्म में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई।

खेल समाचार

बदलेंगे ओपनर,बदला जाएगा मिडिल ऑर्डर

जिम्बाब्वे के खिलाफ पूरी तरह बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11

टीम इंडिया करो या मरो के सुपर 8 मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम का सामना करने वाली है। इस मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं...

नई दिल्ली,25 फरवरी 2026। टी20 वर्ल्ड कप में इस वक्त टीम इंडिया की स्थिति करो या मरो की हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका से मिली 76 रनों की करारी हार ने भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब गुरुवार को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाला मुकाबला भारत के लिए सेमीफाइनल की रेस में बने रहने का आखिरी रास्ता है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

क्या टीम में होगी अक्षर पटेल की वापसी?

अहमदाबाद में उप-कप्तान अक्षर पटेल को बाहर बिठाना टीम

मैनेजमेंट पर भारी पे गया। वाशिंगटन सुंदर न तो बल्ले से कमाल दिखा पाए और न ही गेंद से कोई विकेट ले सके। चेन्नई की फिरकी पिच को देखते हुए अक्षर पटेल का प्लेइंग 11 में वापस आना लगभग तय माना जा रहा है।

चेन्नई की विकेट पर कुलदीप को मिलेगा मौका?

चेन्नई की पिच पर अक्सर स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है। ऐसे में हो सकता है कि कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में वापसी कर लें। हैरानी की बात है कि कुलदीप यादव को इस टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ एक मैच मिला है। प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह की जगह कुलदीप को टीम में लाया जा सकता है। रिंकू पिछली पांच पारियों में दहाई का आंकड़ा भी मुश्किल से छू पाए हैं ऐसे में मैनेजमेंट गेंदबाजी को मजबूत कर सकता है।

ओपनिंग में दिख सकता है बड़ा बदलाव

टी20 क्रिकेट में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा का बल्ला इस बड़े मंच पर पूरी तरह खामोश है। उन्होंने 4 मैचों में महज 15 रन बनाए हैं और तीन मुकाबलों में तो वो खाता तक नहीं खोल पाए। वहीं तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट भी टीम के लिए सिरदर्द बना हुआ है। चर्चा तेज है कि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया जा सकता है। ऐसे में तिलक वर्मा को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अगर संजू आते हैं तो वो ओपनिंग करेंगे और ईशान किशन नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं।

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन,अभिषेक शर्मा, ईशान किशन विकेटकीपर),सूर्यकुमार यादव (कप्तान),शिवम दुबे,हार्दिक पंड्या,अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव,जसप्रीत बुमराह,अर्शदीप सिंह

ईसीबी का वादा,फ्रेंचाइजी मेरिट के आधार पर खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी

लंदन,25 फरवरी 2026। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और द हंड्रेड में हिस्सा लेने वाली सभी आठ फ्रेंचाइजी ने मिलकर घोषणा की है कि आने वाले सीज़न के लिए खिलाड़ियों का चुनाव पूरी तरह से क्रिकेट की काबिलियत, उपलब्धता और टीम की ज़रूरतों के आधार पर किया जाएगा,और राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लंदन, 25 फरवरी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और द हंड्रेड में हिस्सा लेने वाली सभी आठ फ्रेंचाइजी ने मिलकर घोषणा की है कि आने वाले सीज़न के लिए खिलाड़ियों का चुनाव पूरी तरह से क्रिकेट की काबिलियत, उपलब्धता और टीम की ज़रूरतों के आधार पर किया जाएगा,और राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अभिषेक नंबर 1 स्थान पर कायम,ईशान टी20 आई बल्लेबाज रैंकिंग में टॉप-5 में

दुबई,25 फरवरी 2026। भारत के टी 20 आई खिलाड़ियों ने लेटेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेन्स टी20 आई प्लेयर रैंकिंग में दमदार प्रदर्शन किया है,जिसमें ओपनर अभिषेक शर्मा अपनी टॉप जगह पर बने हुए हैं और विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन टॉप पांच में शामिल हो गए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर, अभिषेक ने टी 20 वर्ल्ड कप की शांत शुरुआत के बावजूद अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाए रखी। वह इंग्लैंड के फिल सॉल्ट से 62 पॉइंट की आसान बढ़त बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान,जो अभी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं, दो स्पॉट ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर आ गए, और करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल की। किशन तीन स्पॉट चढ़कर टी20 आई बैटर रैंकिंग में पांचवें नंबर पर आ गए, और सबसे छोटे फॉर्मेट में उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उनकी यह बढ़त भारत के लिए एक फायदेमंद हफ्ते की हेडलाइन है, जिसमें कई खिलाड़ियों ने अपडेटेड चार्ट में बढ़त हासिल की है। टॉप 10 में भारत की मौजूदगी और मजबूत हुई है, किशन की बढ़त के साथ-साथ दूसरे इंटरनेशनल खिलाड़ियों की अच्छी बढ़त भी देखने को मिली है। साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस 10 पायदान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर आ गए,जबकि अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़द्रान (13वें),वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप (14 वें) और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक (18 वें) ने भी काफी तरक्की की है।

ऑलराउंडर्स की लिस्ट में, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने अपनी टीम को सुपर एट्स में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के बाद नंबर 1 जगह फिर से हासिल कर ली। उन्होंने टॉप पर तेज़ी से बढ़ती टक्कर वाली रेस में पाकिस्तान के सैम अयूब को पीछे छोड़ दिया। भारत के शिवम दुबे को भी दो पायदान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर आ गए, जबकि अफगानिस्तान के अनुभवी मोहम्मद नबी आठवें नंबर पर आ गए। बॉलिंग रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ी अहम जगह बनाए हुए हैं। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ महंगे प्रदर्शन के बावजूद नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं। इस बीच,प्रोटियाज़ के तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश के खिलाफ तीन विकेट लेने और भारत के खिलाफ 2/12 के शानदार प्रदर्शन के बाद 21 पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर आ गए। लिस्ट में नीचे, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड (सातवें) और भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (आठवें) ने काफी सुधार किया है। साउथ अफ्रीका के मार्को जेनसन,वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोटी और इंग्लैंड के बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन ने भी हफ्तों के अच्छे प्रदर्शन के बाद ऊपर की ओर बढ़त हासिल की है।

ऑस्ट्रेलिया 23 साल बाद अगस्त में टेस्ट सीरीज़ के लिए बांग्लादेश की मेजबानी करेगा

सिडनी,25 फरवरी 2026। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को बताया कि ऑस्ट्रेलिया 2003 के बाद पहली बार 13-22 अगस्त तक बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ होस्ट करेगा। पहला टेस्ट 13 अगस्त को डार्विन के मारारा स्टेडियम में शुरू होगा। 2004 में ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका होस्ट करने के बाद से डार्विन में यह पहली बार होगा जब कोई टेस्ट होगा। डार्विन ने 2003 में बांग्लादेश और 2004 में श्रीलंका होस्ट किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2008 के बाद से वहां कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था,जब तक कि पिछले साल अगस्त में साउथ अफ्रीका ने वहां ड्रॉप-इन पिच पर दो टी 20 आई मैच नहीं खेले। दो टेस्ट की सीरीज़ 22 अगस्त को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खत्म होगी। खास बात यह है कि मैके पहली बार टेस्ट होस्ट करेगा, और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाला 12वां वेन्यू बन जाएगा। बांग्लादेश ने 2017 में ढाका में ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट जीत के बाद से उनके साथ लंबे समय का क्रिकेट नहीं खेला है। यह सीरीज़ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 साइकिल का हिस्सा होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आठ मैचों में सात जीत के साथ आगे चल रहा है।

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को कानूनी कवच

'मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम, 2023' लागू

पत्रकारों की सुरक्षा,पंजीयन,त्वरित जांच और दंडात्मक कार्रवाई का कानूनी ढांचा तैयार

न्यूज डेस्क

रायपुर,25 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू 'छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम, 2023' को 2 जून 2023 को राजपत्र में प्रकाशित कर प्रभावी किया गया, यह अधिनियम मीडिया कर्मियों को उनके पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान होने वाले हमले, धमकी,उत्पीड़न और अवरोध से कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

अधिनियम का उद्देश्य

अधिनियम का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्रकार और मीडिया संस्थान बिना भय और दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, कानून में स्पष्ट किया गया है कि मीडिया कर्मियों की सुरक्षा, संरक्षण और शिकायतों के निवारण के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित की जाएगी।

प्रमुख प्रावधान

1. **मीडिया कर्मियों का पंजीयन**
अधिनियम के तहत मीडिया कर्मियों के पंजीयन की व्यवस्था की गई है। पंजीकृत पत्रकारों को अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिलेगा, पंजीयन प्रक्रिया को विनियमित और पारदर्शी बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
2. **राज्य स्तरीय सुरक्षा एवं शिकायत निवारण समिति**
पत्रकारों से संबंधित मामलों की सुनवाई और त्वरित कार्रवाई के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, यह समिति–शिकायतों की जांच करेगी, सुरक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा करेगी, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करेगी, समिति में प्रशासनिक, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
3. **सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार**
यदि किसी पत्रकार को उनके कार्य के कारण धमकी,हमला या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है,तो प्रशासन को तत्काल सुरक्षा प्रदान करनी होगी,अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्रकारों को किसी भी प्रकार की हिंसा या दबाव का सामना न करना पड़े।
4. **दंडात्मक प्रावधान**
मीडिया कर्मियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने, हमला करने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया गया है, दोष सिद्ध होने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान अधिनियम में शामिल है, जिससे निवारक प्रभाव उत्पन्न हो सके।
5. **शासन की जवाबदेही**
सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें, सुरक्षा योजनाओं,त्वरित जांच और कार्रवाई की व्यवस्था के माध्यम से पत्रकारों के हितों की रक्षा की जाएगी।

क्यों जरूरी था यह कानून?

पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों पर हमले, धमकी और दबाव की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसी परिस्थितियों में यह अधिनियम पत्रकारों के लिए कानूनी कवच के रूप में देखा जा रहा है, यह कानून–प्रेस की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगा, पत्रकारों में सुरक्षा की भावना पैदा करेगा।

चुनौतियां और अपेक्षाएं...

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी कानून की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि...पंजीयन प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहती है, शिकायतों का निपटारा कितनी शीघ्रता से होता है, दोषियों पर कितनी कठोर कार्रवाई की जाती है, छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा अधिनियम,2023 को राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो यह न केवल पत्रकारों को सुरक्षा देगा, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी और मजबूत बनाएगा।

बिलासपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

ई-मेल में कैंपस को निशाना बनाने का जिक्र बलौदाबाजार जिला कोर्ट को मिला ईमेल फर्जी निकला

बिलासपुर,25 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट और बलौदाबाजार जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिला है। सुबह इस मैसेज में हाईकोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात लिखी गई थी। जिसके बाद पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सूचना मिलते ही एसएसपी रजनेश सिंह खुद टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लिया गया। एंट्री-एग्जिट पर सख्ती बढ़ा दी गई थी। वहीं, बलौदाबाजार जिला कोर्ट को साइनाइड गैस और आरडीएक्स का इस्तेमाल कर उड़ाने की बात इमेल के जरिए की गई थी। प्रारंभिक जांच में यह ईमेल फर्जी पाया गया है। बलौदाबाजार जिला एवं सत्र न्यायालय को बुधवार सुबह 11:01 बजे यह संदिग्ध ई-मेल मिला। इसमें साइनाइड गैस और आरडीएक्स का इस्तेमाल कर न्यायालय को ब्लास्ट करने की बात कही गई थी।

2 पुलिसकर्मियों की मौत,तेज रफ्तार वाहन ने लिया चपेट में

बलौदाबाजार,25 फरवरी 2026। जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। दोनों ड्यूटी जाने के लिए एक बाइक पर सवार होकर निकले थे। इसी दौरान तेज रफ़्तार वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आरक्षक धर्मेंद्र यादव और प्रशांतधर दीवान की मौत हो गई। इस घटना के बाद बलौदाबाजार पुलिस में शोक की लहर है। भीषण सड़क हादसे में दो जवानों की मौत से परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल है। घटना सुबह 11 बजे की बताई जा रही है। कांस्टेबल प्रशांतधर दीवान और धर्मेंद्र यादव एक बाइक में सवार होकर ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान थाना हथबंद क्षेत्र के उडेला-पौसरी के पास तेज रफ़्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं, आरक्षक धर्मेंद्र यादव की मोके पर ही मौत हो गई। धर्मेंद्र यादव वर्तमान में साइबर सेल में पदस्थ थे और ग्राम परसबोड थाना साजा जिला बेमेतरा के निवासी थी। हादसे में हथबंद निवासी आरक्षक प्रशांतधर दीवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे,जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रिफर किया गया था। उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। आरक्षक प्रशांतधर दीवान हथबंद में तैनात थे और नवागढ़ जिला बेमेतरा के रहने वाले थे। इस घटना के बाद बलौदाबाजार पुलिस में शोक की लहर है। भीषण सड़क हादसे में दो जवानों की मौत से परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों शव को पीएम के लिए भेजकर आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है।

सदन में उठा नशे-गिग वर्कर्स का मुद्दा...चंद्राकर बोले...प्रदेश में 2 लाख ड्रग यूजर

बस्तर को उद्योगपतियों को सौंपे जाने की बात दुष्प्रचार : सीएम शर्मा

रायपुर,25 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और धरमलाल कौशिक ने नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन को असफल बताया है। जबकि गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रशासन के फेल होने के आरोपों को नकारा है। चंद्राकर ने AIIMS और सामाजिक न्याय मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नशीले ड्रग यूजर डेढ़ लाख से 2 लाख हो गई है। जबकि गांजा पीने वाले संख्या 3.8 लाख से 4 लाख है। इसी तरह 10 से 17 साल के 40 हजार से ज्यादा बच्चे और किशोर इन्हेलेंट्स और कफ सिरफ के शिकार हैं। नशे की लत की वजह से मानसिक तनाव के चलते सुसाइड कर रहे हैं। इसमें मृत्यु दर 250 से 300 है। चंद्राकर ने कहा कि प्रशासन इसे रोकने में असफल रहा है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साल 2026 में (31 जनवरी 2026 तक) कुल 146 प्रकरणों में 257 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2025 में 16 आरोपियों की करीब 13.29 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या फ्रीज की

गई है। नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स बनाई है। यह कहना गलत है कि प्रशासन फेल रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि नशा और तस्करी पर ध्यानाकर्षण में चर्चा चल रही थी। तब ही विषय शराब पर भी आ गया। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा...'शराब पर चर्चा लंबी है फिर कर लेंगे, शराब पर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।' गृहमंत्री विजय शर्मा की इस बात पर ही भूपेश बघेल ने तीखे तेवर में कहा... 'सत्र चल रहा है.. कितनी भी लंबी बात हो..कितनी भी दूर जाएगी...जाने दीजिए... और चर्चा कराइए।' वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में कहा कि यह आरोप लगाया जाता है कि बस्तर में नक्सलवाद इसलिए समाप्त किया जा रहा है ताकि उद्योगपतियों को बसाया जा सके। यह बात पूरी तरह दुष्प्रचार है। हम वहां कृषि करना चाहते हैं,सिंचाई का साधन बनाना चाहते हैं। वहां कई वॉटरफॉल है, पर्यटन बढ़ाना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार के कचरे को साफ किया है। अक्सर कहा जाता था कि भ्रष्टाचार के मामलों में छोटी मछलियां पकड़ ली जाती हैं और मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं।

अजय बोले...छत्तीसगढ़ के युवा नशे की चपेट में...

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मैक्सिको में ड्रग तस्कर एलमैंचो के एनकाउंटर के बाद वहां के 12 जिलों में हिंसा भड़क गई है। छत्तीसगढ़ के युवा नशा की चपेट में हैं। रायपुर में हर जगह आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध है। पुलिस आरक्षक भी इस मामले में पकड़ा गया है। इसे रोकने में प्रशासन विफल रहा है। कुछ दिनों पहले रायपुर में गांजे की पैकेजिंग करने वालों को पुलिस ने पकड़ा था और उनके पास ऐसे हाईटेक कैमरे थे, जिससे उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि पुलिस आने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशीली पदार्थों जैसे चरस,गांजा,ब्राउन शुगर,हेरोइन,अफीम,डोडा,नशीली गोलियां की तस्करी पर लगाम लगाना अब असंभव सा हो गया है,अवैध तस्करी की घटनाऐं बढ़ती ही जा रही हैं।

तस्करों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई : चंद्राकर

चंद्राकर ने आगे कहा कि प्रदेश में बीते 4 माह में ही कई तस्करी की घटना घटित हुई हैं। 31 जनवरी, 2025 को राजधानी रायपुर व दुर्ग–भिलाई अंतर्गत ही कई पान की दुकाने सूखे नशे से संबंधित गोगो स्मोकिंग कोन,रोलिंग पेपर और परफेक्ट रोल की बिक्री का मामला सामने आया था। इसके साथ–साथ प्री रोल्ड कोन्स,मंकी किंग,ग्लास बॉन्ग,क्रशर फिल्टर टिप्स फ्लेवर हुक्का कोल,आदि ऑनलाइन बेची जा रही है। बिलासपुर शहर के हर चौक–चौराहे में गांजा, इंजेक्शन,कैप्सूल,सिरप इत्यादि आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

प्रशासन के फेल होने के आरोप गलत : विजय शर्मा

चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के आरक्षक ही ऐसे नशील पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। 11 फरवरी, 2026 को टिकरापारा थाना अंतर्गत आरक्षक द्वारा खुले आम हेरोइन बेच रहा था। प्रशासन इन अवैध तस्करों को रोकने में असमर्थ रहा है। इसके साथ–साथ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई तक नहीं की गई। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मैक्सिको की बात आपने बताई। हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है और ना कभी होगी।

छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव 2026

2 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान आज जारी होगी अधिसूचना....

रायपुर,25 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की दो सीटों के लिए आगामी 16 मार्च को मतदान संपन्न होगा,जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह निर्वाचन कवि तेजपाल सिंह तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त होने के कारण रिक्त हो रही सीटों पर कराया जा रहा है। राज्यसभा की ये दो सीटें छत्तीसगढ़ की राजनीति और दिल्ली के सदन में राज्य के प्रतिनिधित्व के लिहाज से बेहद अहम हैं। वर्तमान विधानसभा के संख्या बल को देखते हुए इन सीटों पर होने वाला चुनाव सत्तापक्ष और विपक्ष के लिए अपनी एकजुटता और रणनीतिक पकड़ दिखाने का बड़ा मौका होगा,

जिसका सीधा असर राज्य की भविष्य की नीतियों पर पड़ता है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार,चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 5 मार्च तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच (संवीक्षा) 6 मार्च को की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मार्च निर्धारित की गई है।

5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा के विरोध में लगी याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने कहा-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षा विभाग लेगा परीक्षा

रायपुर,25 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कक्षा पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा के विरोध में दायर याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर से लगाई गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि, सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग ही लेगा।

इस फैसले के बाद प्रदेश के करीब 6200 निजी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की एकीकृत परीक्षा होगी। परीक्षा में पास-फेल का नियम भी लागू रहेगा। निजी स्कूल संगठन ने आरटीई कानून की धारा 16 और 30 का हवाला देकर परीक्षा का विरोध किया था।

फेल होने पर दोबारा पढ़ेगा स्टूडेंट : लेकिन अदालत में यह स्पष्ट हुआ कि केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2024 को आरटीई कानून में संशोधन कर दिया है। संशोधन के अनुसार, कक्षा पांचवीं और आठवीं में वार्षिक परीक्षा होगी और असफल होने पर छात्रों को उसी कक्षा में रोका जा सकेगा।

महंगी किताबों के नाम पर अवैध वसूली : इस मामले में विकास तिवारी ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कहा कि,कई निजी स्कूल सीजी बोर्ड की मान्यता लेकर सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं और अभिभावकों से महंगी किताबों के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जानी हैं, लेकिन निजी स्कूलों ने वर्षों से इन पुस्तकों का वितरण नहीं किया। आरटीई के गरीब छात्रों को भी महंगी निजी किताबें खरीदने को मजबूर किया गया।

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका: सुनवाई के बाद न्यायाधीश नरेश कुमार चंद्रवंशी ने निजी स्कूल संगठन की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि संशोधित कानून के बाद बोर्ड परीक्षा कराना पूरी तरह वैध है। तिवारी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि,इससे फर्जी सीबीएसई स्कूलों पर लगाम लगेगी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक–अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:–13/सरगुजा/डीएन/2026–2028–मो. 94062–23001,98265–32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)